सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 158, नई दिल्ली । रविवार, 18 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा ।

03 गांधी परिवार में जल्द गूंजेगी शहनाई, राहुल सेहरे में?
06 नशे की बढ़ती लत से समाज खतरे में
08 2 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

नियम तोड़ने वालों सावधान: 14 टीमें... 291 बसें जब्त, परिवहन विभाग सख्त, दिल्ली में इन पांच जगहों पर निगरानी

संजय बाटला

राजधानी दिल्ली में चलने वाली प्राइवेट बसों पर नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उपराज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई करने के लिए 14 टीमों को लगाया गया है।

नई दिल्ली। राजधानी की सड़कों पर निजी बसें नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। यह बसें न केवल क्षमता से अधिक सवारियों को ले जा रही हैं बल्कि अवैध रूप से सामान को भी एक राज्य से दूसरे राज्य ले जा रही हैं। इससे कर चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने अब इस पर लगाने की कवायद शुरू की है। हाल में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में एलजी ने नियमों को तोड़ने वाली निजी बसों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई करने के लिए 14 टीमों को लगाया गया है। बीते सप्ताह की कार्रवाई के दौरान ओवरलोडिंग, परमिट शर्तों का उल्लंघन करने, बेतरतीब जगहों पर रुकने और अवैध रूप से वाणिज्यिक सामान ले जाने पर 291 बसों को जब्त किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि निजी बसों को अनुबंध वाहन के रूप में संचालित करने के लिए परमिट दिया जाता है। इसमें यह होता है कि निजी बसों को पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर अपनी यात्रा शुरू और समाप्त करनी होगी, लेकिन बसों के पास विभिन्न स्थानों पर यात्रियों को लेने या छोड़ने का अधिकार है, लेकिन आमतौर पर बसें यात्रियों के बिठाने और उतारने के लिए अवैध रूप से सड़क किनारे खड़ी होती हैं। इससे यातायात भी प्रभावित होता है।

पांच स्थानों पर हो रही निगरानी

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के पांच स्थानों पर सबसे ज्यादा निजी बसों की आवाजाही होती है। इसमें मजनूं का टीला, अक्षरधाम, आनंद विहार, सरोजिनी नगर और धौला कुआं हैं। इन स्थानों पर विशेष निगरानी के लिए टीमें तैनात की गई हैं। यह टीमें शाम चार बजे से रात 12 बजे तक कार्रवाई कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि परमिट उल्लंघन पर 10,000 रुपये और ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अगर एक से अधिक नियमों को तोड़ने के मामले मिलते हैं तो उन बसों को जब्त भी कर लिया जाता है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

एप देगा समाधान, अवैध पार्किंग का होगा निदान, ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी और एनडीएमसी मिलकर करेंगे तैयार

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दो ट्रैफिक जोन के विशेष पुलिस आयुक्त, परिवहन विभाग के आयुक्त और एमसीडी के अधिकारियों के साथ यातायात की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में एलजी ने सड़कों पर अवैध पार्किंग को दूर करने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली। दिल्ली में जाम का कारण बन रहीं अवैध पार्किंग को खत्म करने के लिए एप तैयार किया जाएगा। इस एप को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) मिलकर विकसित करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एनडीएमसी क्षेत्र में तैनात माली इसका उपयोग करेंगे। उनको सिखाया जाएगा कि इसकी मदद से अवैध पार्किंग को कैसे खत्म किया जा सकता है। बाद में इसका विस्तार पूरी दिल्ली में किया जाएगा।

दरअसल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दो ट्रैफिक जोन के विशेष पुलिस आयुक्त, परिवहन विभाग के आयुक्त और एमसीडी के अधिकारियों के साथ यातायात की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में एलजी ने सड़कों पर अवैध पार्किंग को दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके कारण शहर में जाम की समस्या बनती है। इसे दूर करने के लिए सभी एजेंसियों को ध्यान देने की जरूरत है।

एलजी ने ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी और एनडीएमसी को एप विकसित करने का आदेश दिया। इसकी मदद से अवैध-अनधिकृत रूप से पार्क किए गए वाहनों की तस्वीरें फोन से अपलोड की जा सकेंगी। साथ ही उक्त वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एनडीएमसी क्षेत्र में मालियों को गलत तरीके से खड़े वाहनों की तस्वीरें लेकर अपलोड करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। मालियों को प्रोत्साहित करने के तरीके तलाशे जाएंगे। पार्किंग क्षेत्रों और स्थानों के प्रबंधन में यातायात पुलिस को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एलजी ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित हो कि सभी भारी वाहन बाईं लेन का ही उपयोग करें। इसके अलावा पुलिस को उसके विभिन्न यार्डों में खराब और पुराने पुलिस वाहनों को तेजी से हटाने के लिए परिवहन विभाग के साथ समन्वय करने को भी कहा गया।

सड़क पर खड़ी गाड़ियों का कटेगा चालान

बैठक में बताया गया कि मल्टीलेवल पार्किंग स्थलों का उपयोग उनकी पूरी क्षमता से नहीं किया जा रहा है। गाड़ियां गलियों और सड़कों पर पार्क हो रही हैं। इससे पार्किंग की समस्या बढ़ गई है। इसे दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को चालान काटने का अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी गाड़ियां, इसके लिए तय मल्टीलेवल पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करें। कमला नगर और यूसुफ सराय मार्केट में मल्टीलेवल पार्किंग को इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहन को पार्किंग में छूट मिलेगी

बैठक में कहा गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए पार्किंग फीस में छूट दी जाएगी। इसकी मदद से वाहनों के उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही सड़कों पर बनीं पार्किंग साइट पर प्रचलित एक लाइन में लंबी दूरी की जगह कोणीय (कोण की तरह) पार्किंग सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा करने से गाड़ियों को खड़ा करने और बाहर निकालने के दौरान आने वाली परेशानियों को कम किया जा सकेगा। वहीं तय मल्टीलेवल पार्किंग में डिस्काउंट के जरिये पार्किंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

रक्षाबंधन पर दिल्ली मेट्रो रहेगी मुस्तैद, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाई खास रणनीति

रक्षाबंधन के खास मौके पर दिल्ली मेट्रो ने विशेष इंतजाम किए हैं। डीएमआरसी ने बताया कि अतिरिक्त टिकट काउंटर संचालित करके यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मियों को भी तैनात करेगा। इसके अतिरिक्त कई ट्रेनों को स्टैंडबाय पर रखा जाएगा ताकि बढ़ती भीड़ को किसी तरह की समस्या न हो सके।

नई दिल्ली। रक्षाबंधन के दिन अक्सर मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इसके मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सभी कॉरिडोर के लिए अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें तैयार रखी है, इसलिए सोमवार को रक्षाबंधन के दिन मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर डीएमआरसी अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनों का परिचालन करेगा, ताकि यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो सके।

एनसीआर में मेट्रो का कॉरिडोर करीब 932 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 345 मेट्रो ट्रेनें हैं। इसके अलावा गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो के लिए 12 ट्रेनें हैं, लेकिन प्रत्येक दिन सभी मेट्रो ट्रेनों का परिचालन नहीं होता है। डीएमआरसी का कहना है कि जरूरत पड़ने पर रक्षाबंधन के दिन सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारी मौजूद रहेंगे। ताकि स्टेशनों पर टोकन के भीड़ बढ़ने पर यात्रियों को जल्दी क्यूआर कोड आधारित टिकट उपलब्ध कराया जा सके।

स्टेशनों पर सुरक्षा गार्ड व कर्मचारी तैनात रहेंगे

डीएमआरसी ने यात्रियों को दिल्ली मेट्रो के मोमेंटम 2.0 मोबाइल एप, वन दिल्ली एप, पेटीएम इत्यादि माध्यमों से आनलाइन क्यूआर कोड टिकट खरीदकर मेट्रो में सफर करने का अनुरोध किया है, ताकि काउंटर से टिकट लेने की जरूरत न पड़े। यात्री किराया भुगतान के लिए स्मार्ट कार्ड व एनसीएमसी कार्ड (नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्ड मेट्रो स्टेशनों पर कस्टम केयर काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। यात्रियों की मदद के लिए स्टेशनों पर सुरक्षा गार्ड व कर्मचारी तैनात रहेंगे।

नई दिल्ली से अब 10 मिनट पहले चलेगी तेजस एक्सप्रेस, टूंडला में भी होगा ठहराव

यात्रीगण कृपया ध्यान दें नई दिल्ली से लखनऊ की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या (82501) तेजस एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। अब यह गाड़ी नई दिल्ली से निर्धारित समय से 10 मिनट पहले रवाना हुआ करेगी। रविवार 18 अगस्त से तेजस एक्सप्रेस दोपहर को 3 बजकर 40 मिनट की बजाय 3 बजकर 30 मिनट पर रवाना होगी।

नई दिल्ली। नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। नई दिल्ली से अब यह 10 मिनट पहले रवाना होगी। 18 अगस्त से तेजस एक्सप्रेस नई दिल्ली से अपराह्न 3:40 बजे की जगह 3:30 बजे प्रस्थान करेगी।

तेजस एक्सप्रेस 18 अगस्त से टूंडला जंक्शन पर भी रुकेगी

कई ट्रेनों को नए स्टेशनों पर ठहराव देने का निर्णय किया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 18 अगस्त से टूंडला जंक्शन पर भी रुकेगी। लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस (82501) सुबह 9:40 बजे पहुंचेगी।

परिणाम का आकलन करने के बाद होगा निर्णय-रेलवे

वहीं, नई दिल्ली- लखनऊ तेजस एक्सप्रेस (82502) शाम 5:57 बजे यहां पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों का कहा है कि अभी प्रायोगिक तौर पर दो मिनट का ठहराव देने का निर्णय लिया गया है। परिणाम का आकलन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

रक्षा - बंधन, 19 अगस्त 2024 सोमवार

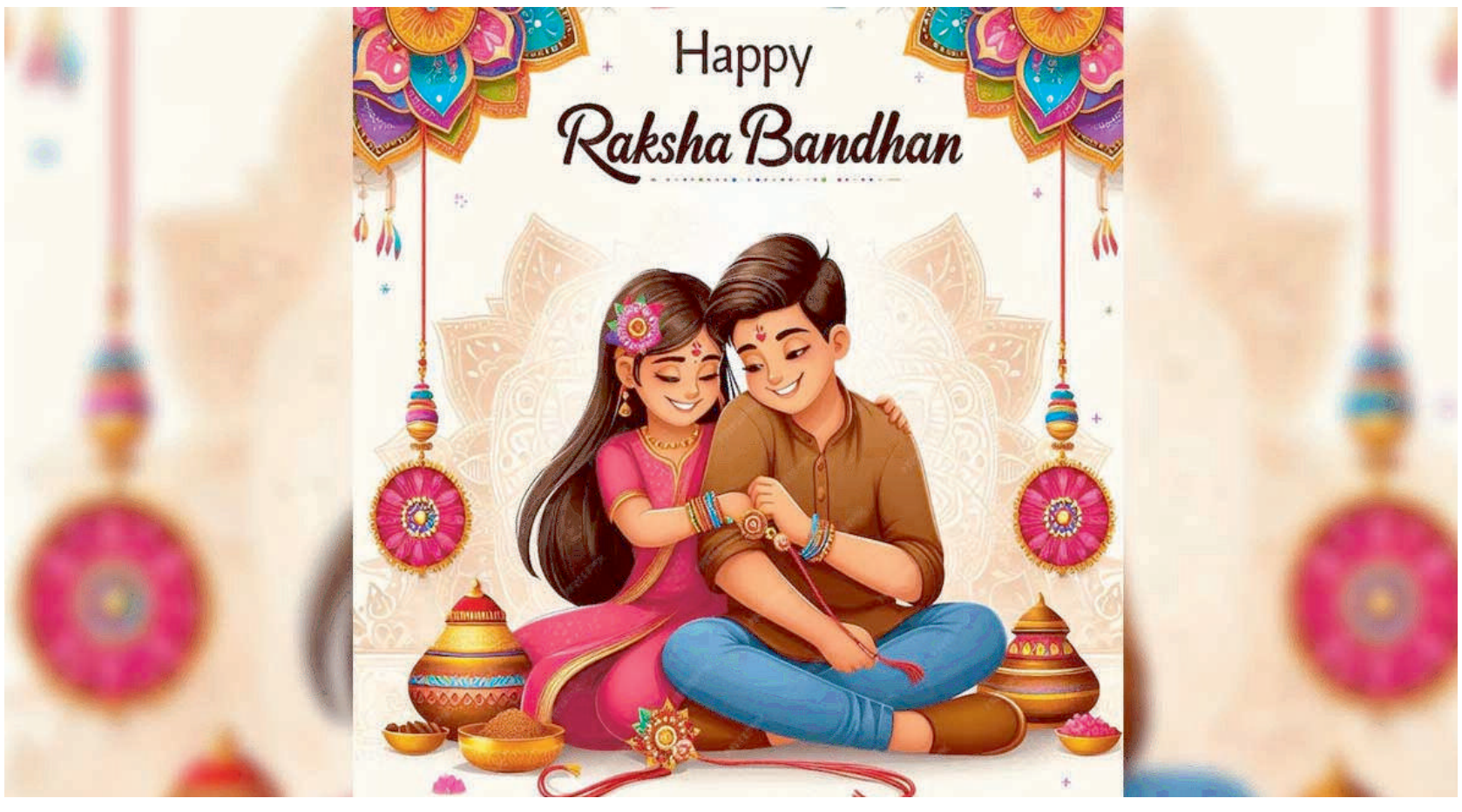

पंचांग के अनुसार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और अबकी बार 19 अगस्त 2024, सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा।

पूर्णिमा तिथि-:

* 19 अगस्त, सोमवार को पूर्णिमा तिथि सूर्योदय से रात्रि 11:56 तक व्याप्त रहेगी।

भद्रा समय-:

* 19 अगस्त, सोमवार के दिन भद्रा प्रातः सूर्योदय से दोपहर 01:35 तक रहेगी।

* इस दिन मकर राशि में चंद्रमा होने के कारण भद्रा पाताल लोक में निवास करेगी, अतः पाताल लोक की भद्रा ज्यादा चिंता जनक नहीं मानी जाती।

शगुन/श्रवन माढ़ने का समय-:

* शगुन रक्षाबंधन के एक दिन पहले अर्थात चतुर्दशी तिथि में मांढे जाते हैं, अतः18 अगस्त, रविवार के दिन सुबह 07:30 से दोपहर 12:24 तक शगुन मांढे जा सकते हैं।

शगुन/श्रवण पूजा (जिमाने) का समय-:

* 19 अगस्त, सोमवार को शुभ का चौघड़िया सुबह 09:10 से सुबह 10:46 तक रहेगा और श्रेष्ठ शुभ अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:50 तक रहेगा अतः इस समय के दौरान शगुन/ श्रवण पूजा का कार्य किया जा सकता है।

रक्षाबंधन का समय/मुहूर्त-:

19 अगस्त 2024, सोमवार

वैसे तो इस बार मकर राशि में चंद्रमा होने की वजह से भद्रा पाताल लोक में रहेगी और पाताल लोक की भद्रा ज्यादा चिंताजनक (अशुभ) नहीं मानी जाती। लेकिन फिर भी भद्रा दोपहर 01:35 पर समाप्त हो जाएगी उसके उपरांत आप राखी बांध सकते हैं।

राखी बांधने का मुहूर्त-:

दोपहर 02:02 से रात्रि 09:05 तक

अवधि-:

लगभग 07 घंटे

रक्षा बंधन अपराह्न मुहूर्त-:

दोपहर 02:02 से शाम 04:19तक।

रक्षा बंधन प्रदोष मुहूर्त-:

शाम 06:56 से रात्रि 09:07 तक।

शुभ- समय चौघड़िया-:

* नीचे दिए गए तीनों चौघड़िये का समय भी रक्षाबंधन के लिए शुभ है-:

चर का चौघड़िया-:

दोपहर02:02 से दोपहर03:40 तक

लाभ का चौघड़िया-:

दोपहर 03:40 से शाम 05:18 तक।

अमृत चौघड़िया-: शाम 05:18 से शाम 06:56

ग्लोइंग स्किन के लिए ये 2 विटामिन हैं फायदेमंद, अगर कमी हुई तो डाउन हो जाएगा निखार

दिव्यांशी भदौरिया

चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए लोग न जाने क्या नहीं करते हैं। फेस मास्क लगाना, पील-ऑफ मास्क लगाना या स्क्रब करना। लेकिन फिर भी चेहरे पर ग्लो नहीं आता है। अगर आपको स्किन ग्लोइंग चाहिए तो आप इन 2 विटामिन का होना जरुरी है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से-

भारत में त्योहारों का सीजन आ चुका है। ऐसे में सभी को चेहरा ग्लोइंग चाहिए होता है। सैलून में जाकर महंगे-महंगे ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन उनमें खतरनाक केमिकल होते हैं जो बाद में स्किन को खराब करते हैं। वहीं, महंगे-महंगे स्किन केयर के प्रोडक्ट खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में स्किन में एलर्जी होने लगती है। अगर आप भी चाहते है कि आपकी स्किन चमकदार दिखें तो इन डाइट में इन 2 विटामिन्स को जरुर शामिल करें।

कौन-सी विटामिन त्वचा को करती है ग्लोइंग

यदि शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाए तो चेहरे पर दाग-धब्बे हो जाते हैं। शरीर की सारी चमक गायब हो जाती है। अगर आप डाइट में विटामिन बी12 एड करें तो स्किन शाइन करती है। विटामिन बी12 शरीर में हीमोग्लोहिन के उत्पादन और शरीर के ऊतकों को ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं, शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाए तो यह हाइपरपिग्मेंटेशन का कारण बन सकता है।

इन चीजों में होती विटामिन बी12

WebMD के अनुसार शरीर में विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप दूध, मछली और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जरूरी है। वहीं, आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर, मशरुम, ओट्स, दही, चीज, सेब, केला और संतरे का सेवन कर सकते हैं।

विटामिन डी

अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो त्वचा रूखी और काली दिखने लगती है। इससे त्वचा का रंग फीका नजर आता है। अगर विटामिन डी कम हो शरीर में, तो डार्क सर्कल दिखने लगते हैं। विटामिन डी त्वचा की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। इस कारण यह जरुरी है कि शरीर में विटामिन डी की कमी न हो।

इन चीजों में होती है विटामिन डी

शरीर में विटामिन डी पाने के लिए आप अंडे, मछली, दूध, दही, पनीर, घी, पालक, मशरुम, अलसी के बीज का सेवन किया जा सकता है। वहीं, आप एवोकाडो, कीवी, अमरूद, पपीता का सेवन कर सकते हैं।

भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन

रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह भाई-बहन को स्नेह की डोर से बांधने वाला त्योहार है। यह त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है'

रक्षाबंधन का अर्थ

रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षाबंधन, अर्थात किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना। इसीलिए राखी बांधते समय बहन कहती है 'भैया! मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी सब प्रकार से रक्षा करना।' आज के दिन बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और उन्हें मिठाई खिलाती है। फलस्वरूप भाई भी अपनी बहन को रुपए या उपहार आदि देते हैं। रक्षाबंधन स्नेह का वह अमूल्य बंधन है जिसका बदला धन तो क्या, सर्वस्व देकर भी नहीं चुकाया जा सकता।

रक्षासूत्र

भारतीय परंपरा में विश्वास का बंधन ही मूल है और रक्षाबंधन इसी विश्वास का बंधन है। यह पर्व मात्र रक्षासूत्र के रूप में राखी बांधकर रक्षा का वचन ही नहीं देता, वरन्‌ प्रेम, समर्पण, निष्ठा व संकल्प के जरिए हृदयों को बांधने का भी वचन देता है। पहले रक्षाबंधन बहन-भाई तक ही सीमित नहीं था, अपितु आपत्ति आने पर अपनी रक्षा के लिए अथवा किसी की आयु और आरोग्य की वृद्धि के लिए किसी को भी रक्षासूत्र (राखी) बांधा या भेजा जाता था। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि 'मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव' अर्थात 'सूत्र' अविच्छिन्नता का प्रतीक है क्योंकि सूत्र (धागा) बिखरे हुए मोतियों को अपने में पिरोकर एक माला के रूप में एकाकार बनाता है। माला के सूत्र की तरह रक्षासूत्र (राखी) भी लोगों को जोड़ता है। गीता में ही लिखा गया है कि जब संसार में नैतिक मूल्यों में कमी आने लगती है, तब ज्योतिर्लिंगम भगवान शिव प्रजापति ब्रह्मा द्वारा धरती पर पवित्र धागे भेजते हैं, जिन्हें बहनें मंगलकामना करते हुए भाइयों को बांधती हैं और भगवान शिव उन्हें नकारात्मक विचारों से दूर रखते हुए दुःख और पीड़ा से निजात दिलाते हैं।

शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन

श्रावण की पूर्णिमा को अपरान्ह में एक कृत्य होता है, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। श्रावण की पूर्णिमा को सूर्योदय के पूर्व उठकर देवों, ब्राह्मणों एवं पितरों का तर्पण करने के उपरांत अक्षत, तिल, धागों से युक्त रक्षा बनाकर धारण करना चाहिए। राजा के लिए महल के एक वर्गाकार भूमि-स्थल पर

जल-पात्र रखा जाना चाहिए, राजा को मंत्रियों के साथ आसन ग्रहण करना चाहिए, वेश्याओं से घिरे रहने पर गानों एवं आशीर्वचनों का तांता लगा रहना चाहिए, देवों, ब्राह्मणों एवं अस्त्र-वस्त्र का सम्मान किया जाना चाहिए, तत्पश्चात राजपुरोहित को चाहिए कि वह मंत्र के साथ 'रक्षा' बांधे और कहे, 'आपको वह रक्षा बांधता हूं जिससे दानवों के राजा बलि बांधे गए थे।' सभी लोगों को, यहां तक कि शूद्रों को भी, यथाशक्ति पुरोहितों को प्रसन्न करके रक्षा-बंधन बंधवाना चाहिए। जब ऐसा कर दिया जाता है तो व्यक्ति वर्ष भर प्रसन्नता के साथ रहता है।

महाभारत की कथा

इस त्योहार का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में मिलता है। महाभारत में कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई तो भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़ कर कृष्ण की उंगली में बांधा था, जिसको लेकर कृष्ण ने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुःशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। तब से 'रक्षाबंधन' का पर्व मनाने का चलन चला आ रहा है।

पौराणिक कथा

भविष्य पुराण में एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार बारह वर्षों तक देवासुर-संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं की हार हो रही थी। दुःखी और पराजित इंद्र, गुरु बृहस्पति के पास गए। वहां इंद्र पत्नी शचि भी थीं। इंद्र की व्यथा जानकर इंद्राणी ने कहा, 'कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा

है। मैं विधानपूर्वक रक्षासूत्र तैयार करूंगी। उसे आप स्वस्तिवाचनपूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। आप अवश्य ही विजयी होंगे।' दूसरे दिन इंद्र ने इंद्राणी द्वारा बनाए रक्षाविधान का स्वस्तिवाचनपूर्वक बृहस्पति से रक्षाबंधन कराया, जिसके प्रभाव से इंद्र सहित देवताओं की विजय हुई। तभी से यह रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें भी भाइयों की कलाई में रक्षासूत्र बांधती हैं और उनके सुखद जीवन की कामना करती हैं।

रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा

मध्यकालीन इतिहास में भी ऐसी ही एक घटना मिलती है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उसके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने उसकी राखी स्वीकार कर ली और उसके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह बहादुरशाह से युद्ध किया। महारानी कर्णावती की कथा इसके लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसने हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा के लिए आमंत्रित किया था। राखी के पवित्र बंधन ने दोनों को बहन-भाई के पवित्र रिश्ते में बांध दिया था। मर्मस्पर्शी कथानुसार, राजपूत राजकुमारी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को गुजरात के सुल्तान द्वारा हो रहे आक्रमण से रक्षा के लिए राखी भेजी थी। यद्यपि हुमायूं किसी अन्य कार्य में व्यस्त था, वह शीघ्र ही बहन की रक्षा के लिए चल पड़ा। परंतु जब वह पहुंचा तो उसे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि राजकुमारी के राज्य को हड़प लिया गया था तथा अपने सम्मान की रक्षा हेतु रानी कर्णावती ने 'जौहर' कर लिया था।

पौराणिक कथा

भविष्य पुराण में एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार बारह वर्षों तक देवासुर-संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं की हार हो रही थी। दुःखी और पराजित इंद्र, गुरु बृहस्पति के पास गए। वहां इंद्र पत्नी शचि भी थीं। इंद्र की व्यथा जानकर इंद्राणी ने कहा, 'कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधानपूर्वक रक्षासूत्र तैयार करूंगी। उसे आप स्वस्तिवाचनपूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। आप अवश्य ही विजयी होंगे।' दूसरे दिन इंद्र ने इंद्राणी द्वारा बनाए रक्षाविधान का स्वस्तिवाचनपूर्वक बृहस्पति से रक्षाबंधन कराया, जिसके प्रभाव से इंद्र सहित देवताओं की विजय हुई। तभी से यह रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें भी भाइयों की कलाई में रक्षासूत्र बांधती हैं और उनके सुखद जीवन की कामना करती हैं।

रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा

मध्यकालीन इतिहास में भी ऐसी ही एक घटना मिलती है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उसके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने उसकी राखी स्वीकार कर ली और उसके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह बहादुरशाह से युद्ध किया। महारानी कर्णावती की कथा इसके लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसने हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा के लिए आमंत्रित किया था। राखी के पवित्र बंधन ने दोनों को बहन-भाई के पवित्र रिश्ते में बांध दिया था। मर्मस्पर्शी कथानुसार, राजपूत राजकुमारी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को गुजरात के सुल्तान द्वारा हो रहे आक्रमण से रक्षा के लिए राखी भेजी थी। यद्यपि हुमायूं किसी अन्य कार्य में व्यस्त था, वह शीघ्र ही बहन की रक्षा के लिए चल पड़ा। परंतु जब वह पहुंचा तो उसे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि राजकुमारी के राज्य को हड़प लिया गया था तथा अपने सम्मान की रक्षा हेतु रानी कर्णावती ने 'जौहर' कर लिया था।

क्यों कहा जाता है भगवान गणेश को एकदंत, इस मंदिर से जुड़ी है कहानी

अनन्या मिश्रा

भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरूआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, गजानन और एकदंत आदि नामों से जाना जाता है।

भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरूआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, गजानन और एकदंत आदि नामों से जाना जाता है। वहीं तमाम भक्त भगवान गणेश की कृपा व आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में जाते हैं। वैसे तो हमारे देश में भगवान गणेश को समर्पित तमाम मंदिर हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको गजानन के उस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर परशुराम और गणेश में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था। जिसके कारण उनका नाम एकदंत पड़ गया था।

3000 फीट की ऊंचाई पर है मंदिर

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बैलाडिला की ढोलकल पहाड़ी पर भगवान श्रीगणेश का यह विशेष मंदिर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। बताया जाता है कि मंदिर में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा ढोलक के आकार की है। जिसके कारण इस पहाड़ी का नाम ढोलकल पड़ गया।

जानिए ढोलकर मंदिर की कथा

पौराणिक कथा के मुताबिक इस पहाड़ी के शिखर पर श्रीगणेश और परशुराम जी में युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान परशुराम के फरसे से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था। जिसकी वजह से उनको गजानन एकदंत कहा जाता है। वहीं परशुराम के फरसे से गणेश जी का दांत टूटा, इसलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे बसे गांव का नाम फरसपाल पड़ गया।

बता दें कि ढोलकट्टा (ढोलकल) की महिला पुजारी से दक्षिण बस्तर के भोगामी आदिवासी परिवार अपनी उत्पत्ति मानते हैं। इसी की याद में छिंदक नागवंशी राजाओं ने शिखर गजानन की प्रतिमा स्थापित की थी। वहीं पुरातत्ववेत्ताओं के मुताबिक इस शिखर पर ललितासन मुद्रा में विराजमान दुर्लभ गणेश भगवान की प्रतिमा करीब 11वीं शताब्दी की बताई जाती है। यहां पर रहने वाले लोग 12 महीने ढोलकर मंदिर में श्रीगणेश की पूजा-अर्चना करते हैं। वहीं फरवरी महीने में यहां पर मेले का आयोजन होता है।

गांधी परिवार में जल्द गूंजेगी शहनाई, राहुल सेहरे में?

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

54 साल की उम्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर शहनाई गूंजने वाली है? राहुल, भारत के सबसे ताकतवर राजनीति परिवार गांधी फैमली के चशमें चिराग है। दरअसल उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन खूब बाते चलती है। कभी कोई मीडिया रिपोर्ट में चर्चा होती है कि उनकी विदेश में कोई गर्लफ्रेंड है। वहीं कभी चर्चा होती है कि राहुल अब जीवन भर शादी नहीं करेगे। इन गर्मा गर्म चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर राहुल की शादी को लेकर एक बार फिर चर्चा चल पडी है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि राहुल जल्द ही शादी करने वाले है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले है।राहुल इसी साल के अंत में शादी कर सकते है। गांधी परिवार में इसे लेकर तैयारियां भी तेज हो चुकी है।दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मां सोनिया गांधी ने राहुल की शादी करने के लिए मनाया है। सोशल मीडिया यूजर्स के दावो को माने तो राहुल की शादी महाराष्ट्र के दिग्गज कांगेस नेता की बेटी से होगी।यह नेता ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में जाना पहचाना नाम है। यह नेता मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुका है।राहुल गांधी की शादी जिस लडकी से होने की चर्चा है वह भी कांगेस की बडी नेता है। बता दे कि वह सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चाए भर है। इन दावों की पुष्टि नहीं करते है।

50 दिन बाद टर्मिनल-एक से शुरू हुई उड़ान सेवा, 28 जून को फोरकोर्ट गिरने के बाद बंद हो गई थी सर्विस

सुषमा रानी

दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल एक से 50 दिन बाद उड़ान सेवा शुरू हो गई। स्पाइसजेट के बाद दो सितंबर से इंडिगो की फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। 28 जून को तेज वर्षा के बाद आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-एक के फोर कोर्ट का हिस्सा गिर गया था। इसके नीचे दबने से एक कैब चालक की मौत हो गई थी। तब से ही टर्मिनल बंद था।

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट के टर्मिनल-एक से 50 दिन के बाद उड़ानों का संचालन शनिवार सुबह से फिर से शुरू हो गया। पहले चरण में स्पाइसजेट एयरलाइंस की उड़ानों का संचालन शुरू किया गया है। दो सितंबर से इंडिगो का संचालन भी शुरू हो जाएगा। 28 जून को तेज वर्षा के बाद आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-एक के फोर कोर्ट का हिस्सा गिर गया था। इसके नीचे दबने से एक कैब चालक की मौत हो गई थी। तब से ही टर्मिनल बंद था।

शनिवार को टर्मिनल एक से 15 उड़ानों का संचालन किया गया। इनमें से आठ उड़ानों को एयरपोर्ट से अलग-अलग राज्यों के लिए जाना था और सात उड़ानों का आईजीआई एयरपोर्ट पर आगमन होना था। जब से टर्मिनल एक बंद हुआ था, तब से यहां की सभी उड़ानों को टर्मिनल दो व तीन से संचालित किया जा रहा था। इस वजह से यहां पर भीड़ काफी बढ़ गई थी। इसे कम करने के लिए इसे दोबारा से खोल दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि इंडिगो एयरलाइंस की 34 उड़ानों का संचालन अगले महीने यानी दो सितंबर से शुरू किया जाएगा।

सबसे ज्यादा विलंब दिल्ली से गोवा जाने वाली उड़ान में

शनिवार को स्पाइसजेट की उड़ानों का टर्मिनल एक से संचालन शुरू हुआ। शनिवार को टर्मिनल एक से धर्मशाला के लिए पहली उड़ान सुबह 11.40 बजे एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय पर उड़ी। वहीं पहले दिन चार उड़ानों का प्रस्थान देरी से हुआ और चार उड़ानें देरी से एयरपोर्ट पहुंची। इनमें से ज्यादातर उड़ानों में ज्यादा विलंब नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विलंब दिल्ली से गोवा जाने वाली उड़ान में देखा गया। सुबह 9.35 बजे इस उड़ान को प्रस्थान करना था, लेकिन उसको करीब दस घंटे की देरी हुई।

शनिवार को स्पाइसजेट की उड़ान से सफर करने वाले यात्रियों ने टर्मिनल एक के भूतल के गेट नंबर ए से एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया व बाहर भी भूतल से ही गए।संभावना यह भी जताई जा रही है कि दो सितंबर से पहली मंजिल के गेट नंबर पांच व छह से यात्रियों को प्रवेश करने दिया जाएगा और वह बाहर भूतल के गेट नंबर ए से ही आ पाएंगे।

इसलिए बंद हुआ था उड़ानों का संचालन

28 जून की सुबह तेज वर्षा की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल एक की छत का हिस्सा उसके पास लगे फोरकोर्ट के लोहे के पिलर सहित नीचे गिर गया था।इसके नीचे चार कार कार दब गई थी। हादसे में एक कैब में बैठे चालक रमेश कुमार की मौत हो गई थी और आठ लोग घायल हो गए थे। इस घटना के कुछ देर बाद टर्मिनल से जुड़ी प्रस्थान की सभी उड़ानों को रद कर दिया गया था। संभावना जताई जा रही है कि छत का हिस्सा छत पर पानी भरने की वजह से गिरा था।

2002 के बाद रिटायर हुए पेंशनर्स के मेडिकल एक्सपेंस उनकी तत्कालीन ट्रांसमिशन, पॉवर जनरेशन कंपनियाँ उठाएगी

सुषमा रानी

नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के रिटायर पेंशनर्स के लिये बड़ा एलान करते हुए उन्हें पैनल अस्पतालों पर कैशलेस सुविधाएँ प्रदान करने की घोषणा की है। शनिवार को बिजली मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये घोषणा की।

इस मौक़े पर बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि, दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स को मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए अब दफ़्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। पैनल अस्पतालों में उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी।उन्होंने कहा कि, केजरीवाल सरकार के इस फ़ैसले से दिल्ली विद्युत बोर्ड के 20,000 से अधिक पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी होगा।

उन्होंने कहा कि, अरविंद केजरीवाल ने हमेशा पेंशनर्स की मुश्किलों को दूर किया। पहले पेंशन को स्ट्रीमलाइन किया तो अब वादा निभाते हुए कैशलेस मेडिकल सुविधाएँ दी है।

बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि, 2002 में दिल्ली के पॉवर सेक्टर में बड़ा रिफार्म हुआ था। दिल्ली विद्युत बोर्ड से बिजली सेक्टर की अलग अलग सेक्टर की इकाइयाँ बनाई गई थी। जिसमें दिल्ली सरकार की बिजली जनरेशन कंपनियाँ, ट्रांसमिशन कंपनी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड और 3 डिस्कॉम्स दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते है।

उन्होंने कहा कि, जब दिल्ली विद्युत बोर्ड की अनबंडलिंग की गई तो जो सरकारी कर्मचारी उस समय दिल्ली विद्युत बोर्ड में काम कर रहे थे, उन्हें सभी सुविधाएँ देने की ज़िम्मेदारी दिल्ली सरकार ने ली थी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए, उनमें से कई कर्मचारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन्हें अक्सर समय से पेंशन नहीं मिलती थी, बाक़ी सुविधाएँ नहीं मिलती थी।

बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनें तब दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स ने उनके सामने अपनी सारी समस्याएँ रखी। और मुझे इस बात की ख़ुशी है कि तब से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली विद्युत बोर्ड के सभी पेंशनर्स के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया गया और सभी ज़रूरतों को पूरा किया गया।

लेकिन एक मुश्किल का सामना अब भी ये पेंशनर्स कर रहे थे। दिल्ली विद्युत बोर्ड में मौजूदा समय में 20,000 से अधिक पेंशनर्स है। जो पेंशनर्स रिटायरमेंट के बाद मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेते थे, उन्हें रिम्बर्समेंट की मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ये प्रक्रिया दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशन ट्रस्ट के माध्यम से होती थी। जब एक बुजुर्ग पेंशनर को एक दफ़्तर से दूसरे दफ़्तर मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है तो वो बहुत परेशान होते थे।

उन्होंने कहा कि, ये पेंशनर्स जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले और अपनी इस समस्या को उनके सामने रखा तो अरविंद केजरीवाल ने हमेशा की तरह उनकी इस समस्या का समाधान करने का वादा किया।और बतौर बिजली मंत्री मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निर्देश मिले कई की ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इन पेंशनर्स को अपने मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट के लिए इधर उधर न भागना पड़े। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि, किसी तरीक़े से इन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधाएँ मिले।

बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि, ₹आज मुझे ये घोषणा करते हुए ख़ुशी है कि, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल सुविधाएँ देने का निर्णय लिया है। अगले 1-2 दिनों में इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा।"

बता दें कि, दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स जो 2002 से पहले रिटायर हुए है, उनके सारे मेडिकल एक्सपेंस को दिल्ली सरकार की कंपनी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड उठाएगी। और 2002 के बाद रिटायर हुए लोगों को, वो जिस ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेशन कंपनी या डिस्कॉम से थे, उनके सारे मेडिकल क्लेम का भुगतान करेंगे।

इन सारी एजेंसीज चाहे तीनों डिस्कॉम्स हो, ट्रांसमिशन या पॉवर जनरेशन कंपनी हो इनका हॉस्पिटलों का एक पैनल है। इन सारे अस्पतालों में दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर्स को ओपीडी, आईपीडी, एडमिशन सुविधाएँ अब 100% कैशलेस माध्यम से उपलब्ध होगी। इन इकाइयों की ज़िम्मेदारी होगी कि वो सभी पेंशनर्स को मेडिकल सुविधाएँ मिले कैशलेश मेडिकल सुविधाएँ मिले।

बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि, ₹मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दिल्ली के हर तबके के लोगों को जब भी किसी दिल्लीवाले कोई कोई परेशानी आई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसे दूर किया है।"

फिल्म के एक दृश्य में ढोल पर लिखे इस्लाम के आखिरी पैगंबर के नाम को लेकर है विवाद

सुषमा रानी

नई दिल्ली: इस महीने के अंत में रिलीज होने वाली फिल्म रद डायरी ऑफ वेस्ट बंगालर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म के एक दृश्य में ढोल की थाप पर नाचते लोगों को दिखाया गया है, और इस ढोल पर मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ है। इस दृश्य को लेकर इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब ने कड़ी नाराजगी जताई है और इसे फिल्म से हटाने की मांग की है।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के अध्यक्ष मौलाना जफरुल हसन ने कहा कि किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और ऐसा कोई भी कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत हों। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आजकल की फिल्मों में क्षणिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए जानबूझकर ऐसे दृश्य डाले जाते हैं, जो बिल्कुल अनुचित हैं।

कार्यक्रम के संयोजक मौलाना हसनअली रजानी ने बताया कि भारतीय सेंसर बोर्ड ने पहले ही फिल्म से कुछ विवादित दृश्यों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद यह आपत्तिजनक दृश्य फिल्म में बरकरार है और फिल्म 30 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दृश्य से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं और यह देश की शांति और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

कार्यक्रम के दौरान उपाध्यक्ष कासिम रिज़वी, महासचिव एस के हैदर और संयुक्त सचिव इमरान ने भी इस विषय पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और भारतीय सेंसर बोर्ड से अपील की कि वह इस विवादास्पद दृश्य को फिल्म से हटाने की गारंटी दे, ताकि मुस्लिम समुदाय में कोई असंतोष न हो।

मेरा घोसला : हमारे जीवन में गौरैया और छोटे पक्षियों का महत्व

हमारा घर हमें जितना सुरक्षित महसूस कराता है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी चिड़िया, आज के इस गर्म और तेजी से बदलते हुए दौर में, अपने आप को कितनी सुरक्षित रख पाती होंगी? माना प्रकृति सभी के लिए कुछ न कुछ करती है, लेकिन हम इंसान हैं, और हमारे लिए पक्षियों को समझना बहुत आवश्यक है।

गौरैया और छोटे पक्षी केवल हमारे आंगन की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारे पर्यावरण और जीवन के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छोटे-छोटे पक्षी हमारे कृषि, बागवानी, और प्राकृतिक वातावरण को संजीवनी देने का काम करते हैं। ये कीड़ों को नियंत्रित करते हैं, परागण में मदद करते हैं, और हमारे वातावरण को संतुलित रखते हैं।

लेकिन, आज के तेजी से बदलते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण, इन छोटे पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। हम अपने जीवन में जिस तरह से बदलाव ला रहे हैं, उससे हमारे नन्हें परिंदों का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है। उनके निवास स्थान खत्म हो रहे हैं, भोजन की कमी हो रही है, और वे शोर-शराबे और प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं।

हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन पक्षियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। हमें अपने घरों, बगीचों, और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये पक्षी सुरक्षित और संरक्षित रह सकें। उदाहरण के तौर पर, हम पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए घोंसले बना सकते हैं, और अपने बगीचों में पक्षियों के अनुकूल पेड़-पौधे लगा सकते हैं।

हमारा यह छोटा सा प्रयास न केवल हमारे जीवन को संवारने में मदद करेगा, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित करेगा। आइए, हम सभी मिलकर अपने स्थानीय पक्षियों के लिए कुछ समय निकालें और इस खास पहल से जुड़ें।

हमारे जीवन में पक्षियों का महत्व अमूल्य है। आइए, अपने नन्हें परिंदों के लिए आवाज उठाएं और उन्हें वह सुरक्षा और प्यार दें जिसकी वे हकदार हैं। पक्षियों को सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य भी। आइए, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारे आस-पास के पक्षी सुरक्षित और संरक्षित रहें।

indiangreenbuddy@gmail.com

पर्यावरण पाठशाला : वेदों से पर्यावरण के प्रति सुंदर शिक्षाएँ और कथन

-डॉ. अंकुर शरण

भारतीय संस्कृति में वेदों का विशेष स्थान है। ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, जिसमें पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी शामिल है। वेदों में प्रकृति को देवता के रूप में सम्मानित किया गया है, और पर्यावरण संरक्षण की कई महत्वपूर्ण शिक्षाएँ दी गई हैं। आइए, वेदों से कुछ सुंदर शिक्षाएँ और कथन जानें, जो हमें पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराते हैं:

1. पृथ्वी और जल का संरक्षण

वेदों में पृथ्वी और जल का विशेष महत्त्व बताया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है:

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।

अर्थ:

आकाश में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधियों में शांति हो।

यह शांति का मंत्र हमें पृथ्वी और जल के संरक्षण की प्रेरणा देता है। वेदों के अनुसार, अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं, तो हर जगह शांति और समृद्धि होगी।

2. वृक्षों का महत्व

वेदों में वृक्षों को देवताओं के समान पूजनीय माना गया है। अथर्ववेद में कहा गया है:

वनस्पते शं नो भव सस्यस्य पतये शं यो भव।

अर्थ:

हे वृक्ष! तुम हमारे लिए शांति का स्रोत हो, हमें अन्न देने वाले हो, हमें शांति प्रदान करो।

यह श्लोक वृक्षों की महिमा को दर्शाता है। वृक्ष केवल फल-फूल और छाया ही नहीं देते, बल्कि हमारी जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत भी हैं। इसलिए वृक्षों का संरक्षण आवश्यक है।

3. जल का महत्व

ऋग्वेद में जल को अमृत कहा गया है:

आपो हि ष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन।

अर्थ:

हे जल! तुम आनंद का स्रोत हो, हमें शक्ति प्रदान करो।

यह श्लोक जल के महत्व को बताता है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे दूषित होने से बचाना चाहिए।

4. प्रकृति से प्रेम और उसका सम्मान

वेदों में प्रकृति से प्रेम और उसका सम्मान करने का संदेश दिया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है:

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।

अर्थः

पृथ्वी मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ।

यह श्लोक पृथ्वी के साथ हमारे अटूट संबंध को व्यक्त करता है। जिस तरह हम अपनी माता का सम्मान और सेवा करते हैं, वैसे ही हमें पृथ्वी का भी सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए।

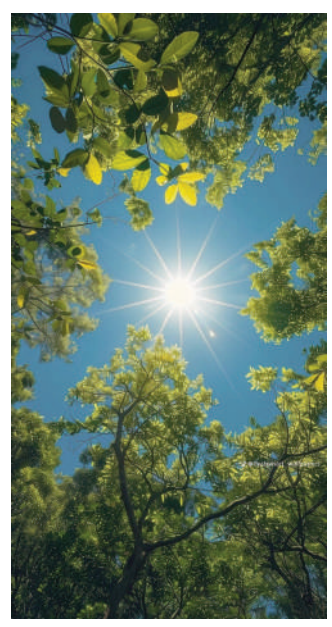

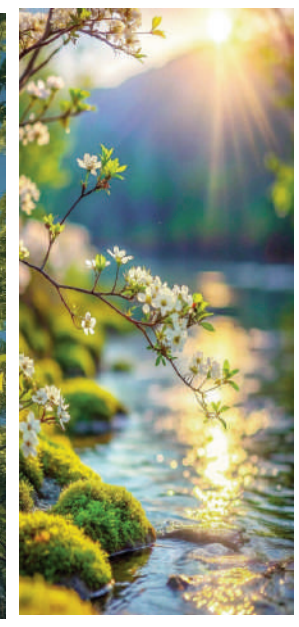

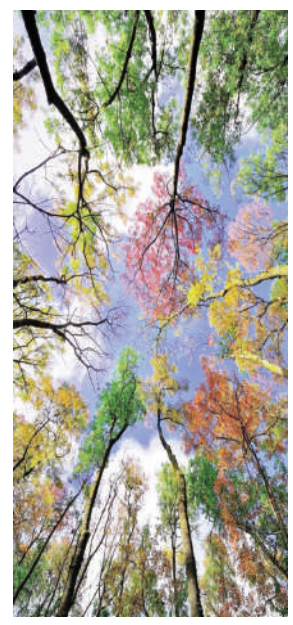

5. वायु का महत्व

वायु को वेदों में जीवनदायिनी शक्ति माना गया है। अथर्ववेद में कहा गया है:

वाताहि दानाय शंसते मे।

अर्थ:

वायु हमारे लिए जीवनदायिनी है, हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है।

यह श्लोक वायु के महत्व को बताता है। स्वच्छ वायु हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।

6. प्रकृति का संतुलन

वेदों में प्रकृति के संतुलन पर विशेष जोर दिया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है:

मित्रस्य चार्षणमित्रस्य हस्तंजिघ्रते।

अर्थ:

सब लोग मित्र की भांति एक-दूसरे का सम्मान करें, एक-दूसरे की सहायता करें।

यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम सभी को प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पृथ्वी, जल, वायु, और सभी जीव-जंतु हमारे मित्र हैं, और हमें उनका संरक्षण करना चाहिए।

वेदों में दी गई ये शिक्षाएँ हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और उसके संरक्षण के महत्व का बोध कराती हैं। हमें इन प्राचीन ग्रंथों की शिक्षाओं को अपनाकर पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण का निर्माण हो सके।

indiangreenbuddy@gmail.com

सौर ऊर्जा से 2,242 घरों को मिली 'रोशनी', हो रही भारी बचत; आप भी करें आवेदन

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सरकार का लक्ष्य उपभोक्ता का बिजली बिल शून्य करना है। जिसके लिए उपभोक्ता को सबसे पहले पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 10 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए विद्युत निगम की तरफ से सीधे अनुमति मिल जाती है। उसके बाद आपको किसी निजी कंपनी से सोलर पैनल लगाकर नेट मीटर खरीदना होगा।

नोएडा। हरित ऊर्जा को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत अब तक 2,242 लोग सोलर पैनल लगाकर हरित ऊर्जा पर शिफ्ट हो गए हैं। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों के बिजली खर्च को कम कर रहा है।

इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य उपभोक्ता का बिजली बिल शून्य करना है। इसके तहत सोलर पैनल लगाने पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। जिसके लिए उपभोक्ता को सबसे पहले पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 10 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए विद्युत निगम की तरफ से सीधे अनुमति मिल जाती है। उसके बाद आपको किसी निजी कंपनी से सोलर पैनल लगाकर नेट मीटर खरीदना होगा। मीटर की विद्युत निगम परीक्षण करेगा।

मानकों के अनुसार होने पर आपका मीटर लगा कर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा। 10 किलोवाट से अधिक की स्थिति में विद्युत निगम की तरफ से आपका फिजिबिलिटी सर्वे किया जाएगा। पर्याप्त जगह होने पर ही आपको अनुमति मिलेगी। मीटर की प्रक्रिया वही रहेगी। आपको विद्युत सुरक्षा विभाग से भी एनओसी लेनी होगी।

अधिक उत्पादन होने पर 3.65 रुपये की दर से रिटर्न

सोलर सिस्टम से अधिक ऊर्जा पैदा होने पर यह विद्युत निगम के उपकेंद्र में चली जाती है। इसके लिए विद्युत निगम उपभोक्ता को 3.65 रुपये की दर से भुगतान करेगा। भुगतान के तीन माध्यम होते हैं। पहला नेट मीटरिंग में यूनिट टू यूनिट ऊर्जा की गणना होती है। इसमें अतिरिक्त यूनिट पैदा होती हैं। वह अगले माह के बिल में समायोजित हो जाती है। इसके बाद मार्च में गणना की जाती है।

अतिरिक्त यूनिट होने पर निगम भुगतान करता है। दूसरा नेट बिलिंग में प्रति माह अतिरिक्त ऊर्जा के लिए भुगतान किया जाता है। अगर आपकी खपत अधिक है तो आपको बिल भी देना होगा। तीसरी श्रेणी में वह उपभोक्ता आते हैं, जो केवल बेचने के लिए सोलर पैनल लगाते हैं। उनको प्रति माह भुगतान किया जाता है।

आरडब्ल्यूए भी कर रही प्रोत्साहित

शहर में स्वच्छ व हरित ऊर्जा के लिए विद्युत निगम आरडब्ल्यूए का भी सहायता ले रहा है। सेक्टर-51 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि उनके घर पर आठ किलोवाट का सोलर सिस्टम लग गया है। साथ ही उन्होंने कई लोगों का आवेदन कराया है व उनका सोलर सिस्टम लगने की प्रक्रिया में है। सेक्टरों में कई लोग सोलर पैनल लगाने के लिए तैयार है। इसके लिए विद्युत निगम के साथ भी वार्ता हो चुकी है।

प्रधामंत्री सूर्योदय योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी मिल रही है। साथ ही जो खर्च आता है। वह बिजली में कटौती होने से एक वर्ष में ही कवर हो जाता है। जिन भी उपभोक्ताओं को पास छत है। वह आवेदन कर सकते हैं। -हरीश बंसल, मुख्य अभियंता विद्युत निगम

बच्ची का पोस्टमॉर्टम कराने के लिए कब्र से निकाला शव, मेरठ में हत्या; गाजियाबाद में दोबारा होगा पीएम

मेरठ में हुई बच्ची की हत्या के मामले में शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के लिए परिजनों ने हंगामा किया। गाजियाबाद के हरबंस नगर निवासी बच्ची स्वजन के साथ मामा की शादी में 15 जुलाई को मेरठ गई थी। वहां से अगवा कर हत्या की गई थी। परिजन गाजियाबाद में ही बच्ची के शव का पोस्टमॉर्टम कराने की मांग पर अड़े रहे।

गाजियाबाद। नंदग्राम थानाक्षेत्र निवासी तीन वर्षीय मासूम बच्ची की 15 जुलाई की देर रात मेरठ में हत्या कर दी गई थी। बच्ची के स्वजन की मांग पर शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया जाना है। शनिवार को मेरठ से आए चिकित्सकों की टीम शव ले जाने के लिए गाजियाबाद आई थी, लेकिन स्वजन ने मेरठ में पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया।

स्वजन गाजियाबाद में ही पोस्टमॉर्टम कराने की मांग कर रहे थे। पीएम दोबारा गाजियाबाद में ही कराने को लेकर हिंडन स्थित मोर्चरी पर शाम को काफी देर तक हंगामा हुआ। रविवार को शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम गाजियाबाद में ही कराने पर स्वजन शांत हुए।

पिता के साथ बच्ची गई थी बारात

हरंबस नगर निवासी तीन साल की बच्ची अपने स्वजन के साथ 15 जुलाई को मेरठ में गई थी। बच्ची के मामा की बारात भावनपुर थाने के दतावली पहुंची थी। बारात में बच्ची भी पिता के साथ गई थी। रात में बच्ची के पिता शादी समारोह में व्यस्त थे। काफी देर तक बेटी नहीं दिखी तो बाराती और घराती समेत गांव वालों ने साथ मिलकर बच्ची की खोज शुरू की। न मिलने पर पुलिस को सूचना दी।

शादी समारोह से दो किमी दूर मिला शव

16 जुलाई की सुबह शादी समारोह स्थल से करीब दो किलोमीटर दूर बच्ची का शव चाकुओं से गुदा हुआ मिला। बच्ची के पिता का कहना है कि इस मामले में मेरठ पुलिस की जांच से वह संतुष्ट नहीं हैं। मेरठ में हुए पोस्टमॉर्टम में बच्ची की मौत की वजह किसी जानवर द्वारा काटने की वजह से बताई गई।

कब्र से निकाल का शव

उन्होंने 18 जुलाई को ही डीएम मेरठ से दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग की थी। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण बच्ची के शव का पोस्टमॉर्टम कराने में देरी हुई। डीएम मेरठ द्वारा 26 जुलाई को दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिए जाने के बाद भी कई दिन तक पीएम नहीं हुआ। शनिवार को मेरठ से आई टीम ने बच्ची के शव को दोबारा पीएम के लिए कब्र से निकाला था।

गाजियाबाद में ही पीएम कराने की मांग

टीम शव को मेरठ लेकर जाने लगी तो स्वजन ने विरोध कर दिया। बच्ची के पिता का कहना है कि दोबारा पोस्टमॉर्टम हम मेरठ में क्यों कराने दें जब मेरठ की टीम ने पहली बार हुए पोस्टमॉर्टम में शरीर पर 22 बार चाकू के वार को जानवर काटने का निशान बताया है। इसलिए हमने गाजियाबाद में ही पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की है। रविवार को अब गाजियाबाद में ही पीएम होगा।

स्वजन दोबारा पोस्टमॉर्टम मेरठ की जगह गाजियाबाद में ही कराने की मांग पर अड़े हुए थे। उनकी मांग पर अब पोस्टमॉर्टम रविवार को गाजियाबाद में ही होगा। -रवि कुमार सिंह, एसीपी नंदग्राम

दिल्ली-NCR में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, IMD ने बताया- अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सोमवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इस वजह से दो दिन उमस भरी गर्मी रह सकती है। इसके बाद तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। वहीं शनिवार को हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में बरकरार रही।

नईदिल्ली। राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस वजह से उमस भरी गर्मी भी महसूस की गई। लेकिन बाद में दिल्ली के कई इलाकों में हल्की वर्षा हुई। नरेला में मध्यम स्तर की सबसे अधिक वर्षा हुई।

इस वजह से मौसम विभाग शाम के वक्त शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी करना पड़ा। जबकि पहले से कोई अलर्ट जारी नहीं था। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में बहुत हल्की वर्षा हो सकती है।

दो दिन उमस भरी गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सोमवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इस वजह से दो दिन उमस भरी गर्मी रह सकती है। इसके बाद तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।

दिल्ली का तापमान दो डिग्री सेल्सियस अधिक

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस से अधिक है। न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक नरेला में मध्यम स्तर की 33 मिलीमीटर वर्षा हुई। पालम इलाके में 10.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

इसके अलावा रिज एरिया में 2.4 मिलीमीटर, दिल्ली विश्वविद्यालय में दो मिलीमीटर, नजफगढ़ में 1.5 मिलीमीटर, पीतमपुरा में 1.5 मिलीमीटर, लोधी रोड में 0.5 मिलीमीटर, सफदरजंग सहित कई अन्य इलाकों में भी हल्की वर्षा हुई। दिल्ली में इस माह अब तक 240.2 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य (131.9 मिलीमीटर) से 108.3 मिलीमीटर अधिक है।

हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में बरकरार

दिल्ली में शनिवार को हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में बरकरार रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में ही बनी रहेगी। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 74, फरीदाबाद का 91, गाजियाबाद 68, गुरुग्राम का 100 व नोएडा का एयर इंडेक्स 80 रहा।

'बम प्लांट कर दिया है सभी लोग मरेंगे', ईमेल देखते ही उड़े एंबिएंस मॉल के अधिकारियों के होश; पुलिस कर रही जांच

गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल में उस समय हड़कंप मच गया जब आज सुबह करीब 1030 बजे यहां पर बम होने की खबर मिली। मॉल प्रबंधन के पास धमकी भरा एक ई-मेल आया। जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसी को इस संबंध में जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल बम निरोधक दस्ता की टीम जांच में जुटी है।

गुरुग्राम। डीएलएफ फेज 3 थाना क्षेत्र स्थित एंबिएंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। शनिवार सुबह 10:30 बजे इसको लेकर मॉल प्रबंधन के पास धमकी भरा एक ईमेल भेजा गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम मॉल में जांच के लिए पहुंची हुई है।

देश भर के मॉल को भेजा गया इस तरह के ईमेल

अभियान चलाया जा रहा है। डीएलएफ फेज 3 थाना प्रभारी का कहना है कि मेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जांच की गई है, अभी तक ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इस तरह के ईमेल देश भर के मॉल को भेजा गया है।

दो महीने पहले पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी

मामले की जांच चल रही है। जल्द ही यह पता लगाया जाएगा कि ईमेल कहां से और क्यों भेजा गया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बता दें दो महीने पहले गुरुग्राम के पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।

हालांकि इस तरीके का धमकी भरा मैसेज नोएडा स्थित डीएलएफ मॉल (dlf mall) को भी आने की बात हो रही थी। जो अभवाह निकली। यहां पर अफवाह या थ्रैट (bomb threat) का कोई प्रभाव नहीं है। लोग अंदर और बाहर आसानी से आ जा रहे हैं।

अंततः अखंड भारत का सपना होगा साकार

प्रह्लाद सबनानी

प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित लगभग समस्त क्षेत्रों में भारतीय सनातन संस्कृति का दबदबा था। भारत को उस खंडकाल में सोने की चिड़िया कहा जाता था।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त 2024 को पूरे भारतवर्ष में 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूम धाम से मनाया गया। दरअसल, भारतीय नागरिक 15 अगस्त 1947 के पूर्व अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत पराधीन थे एवं 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से मुक्त होकर भारतीय नागरिक स्वाधीन हुए। इसलिए इस पर्व को स्वाधीनता दिवस कहना अधिक तर्कसंगत होगा। स्वतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलाकर बना है (1) स्व; एवं (2) तंत्र। अर्थात स्वयं का तंत्र, इसलिए स्वतंत्रता दिवस कहना तो तभी न्यायोचित होगा जब स्वयं का तंत्र स्थापित हो। भारत के नागरिकों में आज "स्व" के भाव के प्रति जागृति तो दिखाई देने लगी है और वे "भारत के हित सर्वोपरि हैं" की चर्चा करने लगे हैं। परंतु, भारत में तंत्र अभी भी मां भारती के प्रति समर्पित भाव से कार्य करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कभी कभी असामाजिक तत्व अपने भारत विरोधी एजेंडा पर कार्य करते हुए दिखाई दे जाते हैं और भारत के विभिन्न समाजों में अशांति फैलाने में सफल हो जाते हैं। स्व के तंत्र के स्थापित होने से आशय यह है कि देश में हिंदू सनातन संस्कृति का अनुपालन सुनिश्चित हो।

प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित लगभग समस्त क्षेत्रों में भारतीय सनातन संस्कृति का दबदबा था। भारत को उस खंडकाल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से पूरे विश्व से विद्यार्थी भारत में आते थे। भारत पर शक, हूण, कुषाण एवं यवन के आक्रमण हुए, परंतु भारत पर उनके कुछ समय के शासन के पश्चात वे भारतीय सनातन संस्कृति में ही रच बस गए एवं भारत का हिस्सा बन गए। परंतु, अरब के देशों से मुसलमान एवं ब्रिटेन से अंग्रेजों के भारत पर चले शासन के दौरान उन्होंने भारतीय नागरिकों का बलात धर्म परिवर्तन करवाया, स्थानीय नागरिकों पर अकल्पनीय अत्याचार किए। भारत के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों, मंदिरों एवं ज्ञान के स्थानों को नष्ट किया। अंग्रेजों ने तो भारतीय नागरिकों के साथ छल कपट करते हुए यह भ्रम फैलाया कि अंग्रेजों ने ही भारतीय नागरिकों को जीना सिखाया है अन्यथा भारतीय समाज तो असभ्य, अनपढ़ गंवार था। उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति पर गहरी चोट की। वे भारतीयों में हीन भावना भरने में सफल रहे। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को नष्ट किया। गुरुकुल नष्ट किए। अंग्रेजों को नौकर चाहिए थे अतः तात्कालिक शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए। इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली देश में आज भी चल रही है, जिसके अंतर्गत शिक्षित भारतीय केवल नौकरी करने के लिए ही उतावाले नजर आते हैं। वे अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के प्रति रुचि ही प्रकट नहीं करते हैं। भारत में उद्योगपति अपने परिवार की विरासत से ही निकले हैं।

भारत को आक्रांताओं एवं अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से समय समय पर भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों ने युद्ध भी लड़े एवं अपने स्तर पर उस खंडकाल में सफलता भी अर्जित की। जैसे, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा आदि के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार, अंगेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले वीर क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के नाम सहज रूप से लिए जा सकते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर मशाल आगे लेकर चलने वाले कई योद्धाओं में महात्मा गांधी, सरदार पटेल एवं सुभाषचंद्र बोस भी शामिल रहे हैं। इसी समय में विवेकानंद एवं डॉक्टर हेडगेवार ने भी सांस्कृतिक चिंतक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन सफलतापूर्वक किया था। इस प्रकार, अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली एवं भारतीय नागरिकों को स्वाधीनता प्राप्त हुई। भारत के लिए यह एक नई सुबह तो थी परंतु यह साथ में विभाजन की त्रासदी भी लेकर आई थी। पूर्व एवं पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में एक नए देश ने भी जन्म लिया और इस दौरान करोड़ों नागरिकों ने अपनी जान गवाईं थी।

आखिर भारत का विभाजन हुआ क्यों? यदि इस विषय पर विचार किया जाय तो ध्यान में आता है कि दरअसल अंग्रेजों ने यह भ्रम फैलाया कि भारत में आर्य बाहर से आए हैं और इस प्रकार वे भारतीय नागरिकों में मतभेद पैदा करने में सफल हुए। साथ ही, उन्हें भारतीय नागरिकों में यह भाव पैदा करने में भी सफलता मिली कि भारत एक भौगोलिक इकाई है एवं यह कई राज्यों को मिलाकर एक देश बना है जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई होती है न कि भौगोलिक इकाई। उस खंडकाल विशेष में अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया मुस्लिम तुष्टिकरण भी भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रवादी मुसलमानों की उपेक्षा की गई थी एवं उस समय की जनभावना को बिलकुल ही नकार दिया गया था, इसके उदाहरण के रूप में 'वन्दे मातरम' कहने पर अंकुश लगाना एवं राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भगवा ध्वज को स्वीकार नहीं करना, का वर्णन किया जा सकता है। और फिर, उस समय विशेष पर भारत का नेतृत्व भी मजबूत हाथों में नहीं था। उक्त कई कारणों के चलते भारत को विभाजन की विभीषिका को झेलना पड़ा था और करोड़ों नागरिक इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे।

वैसे तो भारत को पूर्व में भी खंडित किया जाता रहा है परंतु वर्ष 1947 में हुआ विभाजन सबसे अधिक वीभत्स रहा है। वर्ष 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था, वर्ष 1914 में तिब्बत को भारत से अलग कर दिया गया था, वर्ष 1906 में भूटान एवं वर्ष 1904 में नेपाल को भारत से अलग कर दो नए देश बना दिये गए थे एवं वर्ष 1876 में अफगानिस्तान ने नए देश के रूप में जन्म लिया था। यह सभी विभाजन भारत को पावन भूमि को विखंडित करते हुए सम्पन्न हुए थे। यह सिलसिला

वर्ष 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भी रुका नहीं एवं वर्ष 1948 में भारत के भूभाग को विखंडित कर श्रीलंका के रूप में नए देश का जन्म हुआ। वर्ष 1948 में ही पाकिस्तान के कुछ कबीलों ने भारत के कश्मीर क्षेत्र पर आक्रमण कर कश्मीर के एक हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे आज 'पाक आकुपाईड कश्मीर' कहा जाता है। वर्ष 1962 में आक्साई चिन भी भारत से विखंडित हो गया था।

उक्त विखंडित हुए भूभाग से भारत का नाता आज भी बना हुआ है। जैसे, अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित रही हैं, जिन्हें बाद के खंडकाल में तालिबान ने खंडित कर दिया है। महाभारत काल में गांधारी आज के अफगानिस्तान राज्य की निवासी रही है। अफगानिस्तान शिव उपासना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसी प्रकार पाकिस्तान में तो तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा है, जिसमें विश्व के अन्य देशों से विद्यार्थी अधय्यन के लिए आते थे। हिंगलाज माता का मंदिर है, भगवान झूलेलाल का अवतरण इस धरा पर हुआ था, साधु बेला, संत कंवरराम, ऋषि पिंगल, ऋषि पाणिनि भी इसी धरा पर रहे हैं। भगत सिंह, लाला लाजपत राय एवं आचार्य कृपलानी जैसे देशभक्तों ने भी इसी धरा पर जन्म लिया था। बंगला देश में भी आज ढाकेश्वरी मंदिर स्थित है जिसके नाम पर ही बांग्लादेश की राजधानी को ढाका कहा जाता है। जगदीश चंद्र बोस एवं विपिन चंद्र पाल जैसे महान देशभक्तों ने भी इसी धरा पर जन्म लिया है। नेपाल तो अभी हाल ही के समय तक हिंदू राष्ट्र ही रहा है एवं यहां पर कैलाश मानसरोवर, पशुपति नाथ मंदिर, जनकपुर जहां माता सीता का जन्म हुआ था एवं विश्व प्रसिद्ध लुम्बिनी, आदि नेपाल में ही स्थित हैं। इस दृष्टि से यह ध्यान में आता है कि भारत को एक बार पुनः अखंड क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि भारत से अलग हुए इन सभी देशों की सांस्कृतिक विरासत तो एक ही दिखाई देती हैं।

महर्षि अरविंद तो कहते ही थे कि भारत अखंड होगा क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है। स्वामी विवेकानंद जी को भरोसा था कि भारत एक सनातन राष्ट्र के रूप में अखंड होगा ही। आज हम सभी भारतवासियों को यह विश्वास अपने मन में जगाना होगा कि भारत एक अखंड राष्ट्र होगा ही इसके लिए मेहनत की पराकाष्ठा जरूर करनी होगी। हिंदू एक संस्कृति है न कि पूजा पद्धति, इस प्रकार का व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अखंड भारत में समस्त मत पंथों को मानने वाले नागरिकों को अपनी पूजा पद्धति के लिए छूट होगी ही। इस संदर्भ में विघटनकारी सोच की राजनैतिक पराजय अति आवश्यक है। भविष्य में केवल भारत ही अखंड होगा, ऐसा भी नहीं है। इसके पूर्व एवं पश्चिमी जर्मनी एक हो चुके हैं, वियतमान में भी इसी संदर्भ में बाहरी षड्यंत्र विफल हो चुके हैं। इजराईल देश भी तो अनवरत साधना से ही बन पाया है, फिर भारत क्यों नहीं अखंड हो सकता।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

युलु ने पांडिचेरी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेवा शुरू की

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रीन ड्राइव पांडिचेरी शहर में युलु के मिरेकल ईवी का संचालन करेगा। यह लॉन्च युलु की बिजनेस पार्टनर पहल का हिस्सा है, जिसने पहले इंदौर, कोच्चि और तिरुनेलवेली में सेवाएँ स्थापित की हैं।

अपने पर्यटक आकर्षणों के लिए मशहूर पांडिचेरी को यातायात और प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। युलु के ईवी को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प के रूप में पेश किया जाता है जिसके लिए ड्राइवर के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटा है।

युलु के सह-संस्थापक और सीईओ अमित गुप्ता ने कहा कि यह लॉन्च भारत में गैर-मेट्रो शहरों को स्थायी रूप से बदलने के उनके मिशन के अनुरूप है। ग्रीन ड्राइव पांडिचेरी के संस्थापक के. प्रकाशेश ने स्थायी पर्यटन पर साझेदारी के संभावित प्रभाव के बारे में आशा व्यक्त की।

ईवी पांडिचेरी में पर्यटकों और अवकाश यात्रियों के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विशिष्ट स्थानों पर उपलब्ध होंगे। युलु ने ईवी, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और स्थानीय आतिथ्य खिलाड़ियों के साथ संबंधों के संदर्भ में सहायता प्रदान की है।

युमा द्वारा स्थापित एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बेड़े की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

यह लॉन्च युलु के दसवें शहर में विस्तार को चिह्नित करता है, जिसका परिचालन अब कंपनी के स्वामित्व वाले और फ्रेंचाइजी संचालित दोनों मॉडलों के तहत कई प्रमुख भारतीय शहरों में फैल रहा है।

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने भारत में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए वर्टेलो के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (टीपीईएम), जिसे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्रांति में अग्रणी माना जाता है, ने 2,000 XPRES-T ईवी की डिलीवरी के लिए मैक्वेरी द्वारा प्रबंधित एकीकृत फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन प्लेटफॉर्म वर्टेलो के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के संधारणीय ई-मोबिलिटी में बदलाव को गति देने की योजनाओं को मजबूत करना है। कंपनी चरणबद्ध तरीके से वर्टेलो को कारों की डिलीवरी शुरू करेगी।

साझेदारी पर बोलते हुए, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी, श्री विवेक श्रीवत्स ने कहा, "भारत में यात्री ईवी के बाजार के नेताओं के रूप में, हम देश में स्थायी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत में ईवी अपनाने को बढ़ाने के उनके प्रयास में वर्टेलो के साथ साझेदारी करके हमें खुशी हो रही है। वित्त वर्ष 24 में 89% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ, बेड़े खंड में कॉर्पोरेट्स और संस्थानों द्वारा तेजी से अपनाया गया है। XPRES-T EV वाणिज्यिक बेड़े खंड में ग्राहकों और ऑपरेटरों दोनों के लिए एक आकर्षक विकल्प साबित हुआ है। उद्योग में इस तरह के सहयोग भारत की ईवी क्रांति के बीच हमारी बाजार स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेंगे।"

साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए, वर्टेलो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संदीप गंभीर ने

कहा कि ₹हम 2,000 इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने के लिए इस दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी पर टाटा मोटर्स के साथ साझेदारी करके वास्तव में उत्साहित हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य दो व्यवसायों को एक साथ लाना है जो भारत में फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन और डीकार्बोनाइजेशन के मामले में सबसे आगे हैं। हमें उम्मीद है कि यह साझेदारी फ्लीट ऑपरेटरों के लिए कस्टम लीजिंग विकल्प उपलब्ध कराकर अधिक टिकाऊ भारत की ओर बदलाव को गति देने में मदद करेगी, जिससे उन्हें बड़ी संख्या में ईवी को ऑनबोर्ड करने में मदद मिलेगी।"

जुलाई 2021 में, टाटा मोटर्स ने विशेष रूप से फ्लीट ग्राहकों के लिए 'XPRES' ब्रांड लॉन्च किया, और XPRES-T EV इस ब्रांड के तहत पहला वाहन है। नई XPRES-T इलेक्ट्रिक सेडान 2 रेंज विकल्पों के साथ आती है - 315 किमी और 277 किमी (परीक्षण स्थितियों के तहत ARAI प्रमाणित रेंज)। इसमें 26 kWh और 25.5 kWh की उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बैटरी है और इसे फ़ास्ट चार्जिंग का उपयोग करके क्रमशः 59 मिनट और 110 मिनट में 0-80% तक चार्ज किया जा सकता है या इसे किसी भी 15 A प्लग पॉइंट से भी सामान्य रूप से चार्ज किया जा सकता है, जो आसानी से उपलब्ध और सुविधाजनक है। यह सभी वेरिएंट में मानक के रूप में ज़ीरो टेल-पाइप एमिशन, सिंगल स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डुअल एयरबैग और EBD के साथ ABS के साथ आता है। मानक ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में इलेक्ट्रिक ब्लू एक्सेंट के साथ प्रीमियम इंटीरियर इसे अन्य टाटा कारों से अलग पहचान देगा।

वर्टेलो एक नया प्लेटफॉर्म है जो भारत में फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन में एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है। कंपनी का लक्ष्य फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की प्रक्रिया को तेज करना और ग्राहकों को लीजिंग और फाइनेंसिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा समाधान, फ्लीट प्रबंधन सेवाएं और वाहन के जीवन के अंत के प्रबंधन सहित विशिष्ट समाधान प्रदान करके एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। नया प्लेटफॉर्म मैक्वेरी एसेट मैनेजमेंट द्वारा स्थापित किया गया है और इसे ग्रीन क्लाइमेट फंड से एंकर निवेश प्राप्त हुआ है, जिसने $200 मिलियन तक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। कुल मिलाकर, वर्टेलो संभावित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से 10 वर्षों में $1.5 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर की दो बड़ी कंपनियों की हालत खराब, एक कंपनी बंद होने की कगार पर

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में ईवी सेगमेंट में कभी टॉप पर रहने वाली कंपनियां अब बंद होने की कगार पर हैं। हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और बेनलिंग जैसी कंपनियां बुरे दौर से गुजर रही हैं, जबकि कुछ अन्य स्टार्टअप अपना बिजनेस मॉडल बदल रहे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक के सैकड़ों डीलर जिन्होंने अपना सबकुछ दांव पर लगाकर ईवी क्रांति का हिस्सा बनने का सपना देखा था। हीरो इलेक्ट्रिक देश की पहली कंपनी थी जिसने बड़े पैमाने पर ईवी सेगमेंट में कदम रखा था। लेकिन अब डीलरशिप बंद होने की कगार पर है और अब इनके डीलर्स डीलर सड़क पर या गये हैं।

हीरो और ओकिनावा की बिक्री में गिरावट हीरो इलेक्ट्रिक ने 2021-22 में 70 हजार टू-व्हीलर ईवी बेचे और तब कंपनी का मार्केट शेयर 27 फीसदी था। लेकिन इस साल कंपनी ने सिर्फ 1100 वाहन ही बेचे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर 27 फीसदी से घटकर सिर्फ 1 फीसदी रह गया है।

इसी तरह ओकिनावा ने 2021-22 में 48 हजार दोपहिया वाहन बेचे और कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 19 फीसदी रही। लेकिन इस साल अब तक सिर्फ 1870 वाहन ही बिक पाए हैं। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 19 फीसदी से घटकर सिर्फ 1 फीसदी रह गई है।

सरकार ने इन कंपनियों पर फेम 2 सब्सिडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और इन्हें सब्सिडी योजना से ब्लैकलिस्ट कर दिया। आरोप है कि ये कंपनियां लोकलाइजेशन के नियमों का पालन नहीं कर रही थीं और चीन जैसे देशों से पार्ट्स आयात कर वाहनों की असेंबलिंग कर रही थीं। सरकार ने करीब 450 करोड़ की रिकवरी की भी मांग की है। ईवी स्टार्टअप बेनलिंग भी बंद हो गई है। एक और ईवी कंपनी लोहिया ऑटो ने अपना फोकस दोपहिया से बदलकर तिपहिया वाहनों पर कर लिया है।

चीन समेत दुनिया के बड़े ईवी बाजारों में इससे जुड़े स्टार्टअप धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक से अपना बकाया वापस मांग रहे ये डीलर भारत में ईवी सेगमेंट में मंदी की ओर भी इशारा कर रहे हैं।

इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन वाहनों पर 1 अक्टूबर से सख्त सेफ्टी नियम लागू करेगी सरकार

परिवहन विशेष न्यूज

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने एक अक्टूबर 2024 से डंपर तथा उत्खनन मशीनों सहित इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विनिर्माण उपकरण वाहनों के लिए नए सख्त सुरक्षा मानकों का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना के मसौदे में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।

नियमों के मसौदे में कहा गया, ''1 अक्टूबर, 2024 को और उसके बाद इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से लैस विनिर्माण उपकरण वाहन एआईएस-174 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करेंगे, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता।''

विनिर्माण उपकरण वाहनों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिसूचना के अनुसार, उक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त नियमों के मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

लखनऊ में अब परिवहन विभाग के सभी काम होंगे ऑनलाइन

परिवहन विशेष न्यूज

लखनऊ में 1 सितंबर से परिवहन विभाग के सभी काम ऑनलाइन होंगे। एनआईसी पोर्टल के माध्यम से वाहन मालिक अपने काम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह से लागू थी। विभाग की तरफ से अब वाहन संबंधी सभी काम में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद लखनऊ में रजिस्टर्ड करीब 28 लाख वाहन मालिकों पर इसका असर पड़ेगा। इस दौरान वाहन संबंधी कोई काम कराने पर लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा। अभी तक ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में वाहनों के पंजीकरण और रिन्यूअल होते थे, लेकिन अब वाहन मालिक को अपने काम के लिए आरटीओ पहुंचना होगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद कार्यालय के काउंटरों पर भीड़ नहीं जुटेंगी। कुछ हद तक दलाली पर अंकुश लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है।

एक सितंबर से वाहन से संबंधित मैन्युअल काम बंद हो जाएंगे। जो भी काम कराना होगा उसके लिए वाहन स्वामी को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा और स्लॉट बुक करना होगा। आरटीओ (प्रशासन) संजय

कुमार तिवारी का कहना है कि अभी तक सारथी 4.0 पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी काम ऑनलाइन हो चुके हैं लेकिन वाहन से संबंधित कई ऐसे काम जो बिना स्लॉट बुक किए ही हो रहे थे। वह काम अब एक सितंबर से ऑनलाइन स्लॉट लेने के बाद ही होंगे।

वाहनों का ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन, वाहनों का लोन निरस्त कराने के बाद नई आरसी कॉपी लेने के लिए और वाहन पर लोन को चढ़वाने के लिए अब ऑनलाइन स्लॉट बुक करना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही टैक्स जमा करने की प्रक्रिया में भी ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

किसानों के लिए हुआ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च

ऑटोएनएक्सटी नाम की कंपनी ने देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ऑटोएनएक्सटी एक्स45 बाजार में उतारा है। इस ट्रैक्टर की शुरुआती कीमत 15 लाख रुपये है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं है। हर राज्य के हिसाब से सब्सिडी अलग-अलग होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रैक्टर एक बार चार्ज करने पर करीब 6 घंटे काम करेगा। जबकि सिंगल फेज चार्जर से इसे 6 से 8 घंटे और थ्री फेज चार्जर से तीन घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इस ट्रैक्टर में 32 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। यह 45 एचपी की पावर जेनरेट कर सकता है। ट्रैक्टर में 35KWHr क्षमता का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी दावा कर रही है कि यह ट्रैक्टर हाई टॉर्क और जबरदस्त एक्सीलरेशन देता है। साथ ही, यह बिना शोर के काम कर सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर चलाना डीजल ट्रैक्टर से काफी सस्ता है। डीजल के मुकाबले बिजली की कीमतें कम होती हैं और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का रख-रखाव खर्च भी कम होता है।

इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर प्रदूषण मुक्त होते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है।

इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले काफी कम शोर करते हैं, जिससे किसानों को काम करने में आसानी होती है और आसपास के लोगों को भी परेशानी नहीं होती।

इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में ज्यादा टॉर्क होता है, जिससे भारी काम आसानी से किया जा सकता है।

कई राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देती हैं, जिससे किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने में मदद मिल सकती है।

इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उन्हें चलाना आसान होता है और किसानों को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं।

अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में जल्द शुरू होगा रोप-वे और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

परिवहन विशेष न्यूज

अपने शहरी परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए इटानगर नगर निगम शहर में रोप-वे सिस्टम और इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने जा रहा है. अरुणाचल की राजधानी में जल्द ही रोपवे और इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईटानगर नगर निगम (आईएमसी) के मेयर तम्मे फासांग ने कहा है कि रोप-वे सिस्टम की स्थापना के लिए चर्चा अंतिम चरण में है। आईएमसी परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए हैदराबाद और गुजरात स्थित कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। प्रस्तावित रोप-वे शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक सुंदर और कुशल परिवहन मार्ग प्रदान करेगा, जो डिवीजन 4 में लोबी, सचिवालय, गंगा मार्केट, चिम्पू और इसके विपरीत संचालित होगा।

रोप-वे के अलावा आईएमसी अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा के साथ मिलकर राजधानी शहर में 10 इलेक्ट्रिक बसें चला रहा है, जिसमें भविष्य में विस्तार की संभावना है, हालांकि यह परीक्षणों की सफलता पर निर्भर करेगा। मेयर ने कहा है कि ये विकास आईएमसी के अपने परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने और टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं।

रोप-वे और 10 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से राजधानी में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त होगी। स्थानीय लोगों के साथ राजधानी में आने वाले लाखों पर्यटकों को इसका फायदा होगा। राजधानी में घूमना पहले से कई ज्यादा सुगम होगा और परिवहन व्यवस्था बेहतर होने से समय की बचत भी होगी।

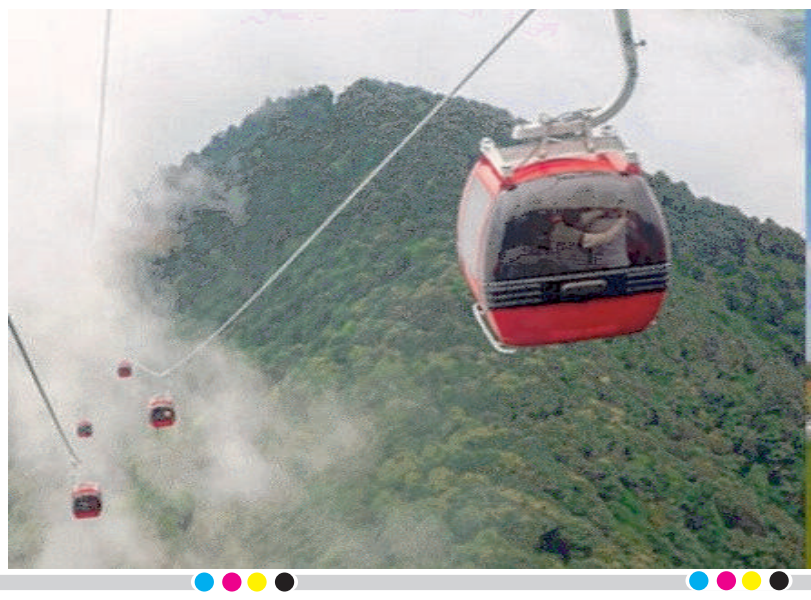

पाक से एक कदम पीछे क्यों रह गया भारत

डा. जयंतीलाल भंडारी

भारत में हर बच्चा किसी पॉप स्टार, किसी फिल्म स्टार या किसी अन्य सेलिब्रिटी को अपना आदर्श मानता है। इस सूची में खेलों में सिर्फ क्रिकेट शामिल है, जोकि बेहद महंगा होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय खेल नहीं है। क्रिकेट एशियाई और ओलंपिक में शामिल नहीं है। युवा यदि थोड़ा-बहुत खेलों के प्रति आकर्षित है भी तो क्रिकेट की तरफ'

भुखमरी-गरीबी और आतंकवाद का शिकार पाकिस्तान 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में आगे रह कर भारत को शर्मिंदा कर गया। देश की एक अरब 40 करोड़ की आबादी और खिलाडियों पर 4 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भारत एक स्वर्ण पदक तक हासिल नहीं कर सका। भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करके पाकिस्तान ओलंपिक की सूची में भारत से आगे निकल गया। खेलों में भारत का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन बताता है कि सिर्फ जीडीपी में पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से इस दिशा में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए खेलों में संसाधनों के साथ खेल संस्कृति का जज्बा जरूरी है। पाकिस्तान ही नहीं, अफ्रीका के ऐसे देश, जो दशकों से घरेलू युद्ध का बेहद गरीबी में सामना कर रहे हैं, वे भी ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेलों के आयोजन में भारत को पछाड़ गए। भारतीय टीम से उम्मीद की गई थी कि वो टोक्यो ओलंपिक से अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम पिछले ओलंपिक से एक मेडल कम रह गई। टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल के मुकाबले पेरिस में 6 मेडल आए हैं। इसमें 5 ब्रांज और एक सिल्वर है। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता। केंद्र सरकार ने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खिलाडियों पर अरबों पर रुपए खर्च किए थे, लेकिन उसका परिणाम सुखद नहीं रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से 16 खेलों में 117 एथलीट गए थे। इस पर भारत सरकार ने कुल 470 करोड़ रुपए खर्च किए थे। एथलेटिक्स के अलग-अलग खेलों के लिए कुल 96.08 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। बैडमिंटन पर 72.03 करोड़, बॉक्सिंग पर 60.93 करोड़, शूटिंग 60.42 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हॉकी पर 41.3 करोड़ और रेसलिंग पर 37.8 करोड़, आर्चरी में 39.18 करोड़ खर्च हुए थे। इसके अलावा वेटलिफ्टिंग, टेबल टेनिस, नौकायन जैसे खेलों पर भी करोड़ों खर्च हुए थे। औसतन एक मेडल के लिए सरकार को 78 करोड़ खर्च करने पड़े। भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में सिल्वर, मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने शूटिंग में ब्रांज, भारतीय हॉकी टीम ने ब्रांज, अमन सहरावत ने कुश्ती में ब्रांज जीता। मनु भाकर ने 2 ब्रांज मेडल जीते थे। दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन वह भारत से मेडल टैली में आगे निकल गया है, क्योंकि मेडल टैली में उसे ऊपर रखा जाता है, जो स्वर्ण पदक जीतता है।

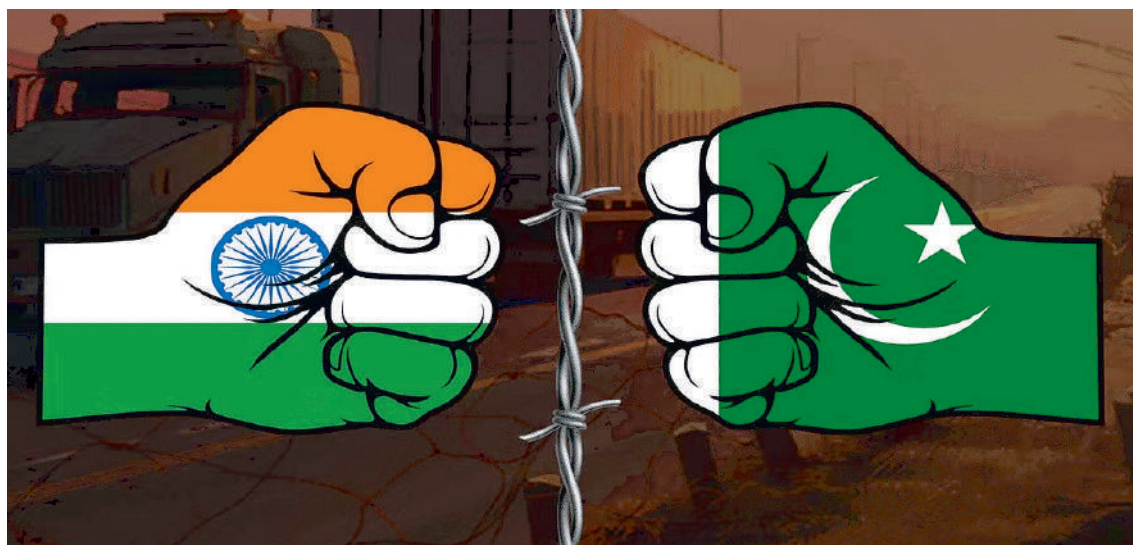

भारत ने पेरिस ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है, जबकि पाकिस्तान के एक गोल्ड जीतते ही लॉटरी लग गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली में भारत 71वें नंबर पर है, तो वहीं पाकिस्तान 62वें नंबर पर मौजूद है। हर विश्व चैंपियनशिप के दौरान भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कई सवाल पूछे जाते हैं। हमारी टीमें अक्सर गुस्साए और निराश दर्शकों के सामने लौटती हैं और हम अपने मेहनती खिलाडियों पर भी अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। खेलों में भारत की दुर्दशा का आलम यह है कि हॉकी के अलावा अन्य टीम वाले खेलों में भारत का विश्व स्तर पर अता-पता तक नहीं है। इसमें महिला टीम के खेलों की हालत और भी ज्यादा शोचनीय है। देश में खेल के लिए पर्याप्त वातावरण नहीं होने के अलावा लैंगिक भेदभाव भी खेलों में भारतीय महिलाओं के पिछडने की प्रमुख वजह है। भारत के ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन का कारण भारत की विश्व स्तर पर खराब रैंकिंग भी है। भारतीय टेनिस टीम विश्व में 23वें स्थान पर है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम 127 देशों में से 34वें स्थान पर है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम 113 खेलने वाले देशों में से 100वें स्थान पर है। भारतीय बास्केटबॉल टीम 85 देशों में से 61वें स्थान पर है। नवीनतम फीबा रैंकिंग रिपोर्ट में हमारी रग्बी टीम 102 खेलने वाले देशों में से 74वें स्थान पर है। सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी आबादी, क्षेत्रफल और अर्थव्यवस्था वाले देश की हालत खेलों के प्रदर्शन में इतनी खराब कैसे है। खेलों की सुविधाओं में निवेश करने की भी जरूरत है। चीन ने ऐसा किया और कमाल का प्रदर्शन किया। ब्रिटेन ने ऐसा किया और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि ने भी यही किया। जाहिर है कि अमेरिका के पास निवेश और एक बड़ी आबादी है जो कई ओलंपिक खेलों के लिए जुनूनी है, इसलिए उनका सामान्य प्रभुत्व है। लेकिन केन्या और इथियोपिया या जमैका जैसे देशों को देखें और जिस तरह से वे आर्थिक रूप से शक्तिशाली न होते हुए भी लगातार विशेष खेलों में विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करने में सक्षम रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने की परंपरा है और उन देशों के बच्चे शायद वहां के लोगों को अपना आदर्श मानते हुए बड़े होते हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया है और जीत हासिल की है।

भारतीय मानसिकता खेलों में खर्च करने के खिलाफ रही है, वह चाहे सरकारी स्तर पर हो या पारिवारिक स्तर पर। इसे व्यर्थ का गैरउत्पादक निवेश माना जाता है। चीनी टेनिस खिलाड़ी झेंग किनवेन, जिसने हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, ने टेनिस खेलना शुरू करने के बाद से अब तक 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च कर दिए हैं। 2.8 मिलियन डॉलर एक चीनी परिवार के लिए कोई छोटी रकम नहीं है, भारतीय परिवार की तो बात ही छोड़िए। यहां तक कि अनुभवी एथलीटों के लिए भी प्रतियोगिता में पुरस्कार राशि जीतने की 100 प्रतिशत गारंटी नहीं होती। चीनी मीडिया का दावा है कि भारत में लडक़ों को खेलों के बजाय डॉक्टर और इंजीनियर बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वहीं चीन में 3 से ज्यादा की उम्र के बच्चे बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इस तकलीफ को सहकर ही वे चैम्पियन बनने की कला सीखते हैं। चीन के पास एक तय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूलों का मॉडल है जिसके जरिए उसका पैसा ट्रेनिंग पर ही खर्च होता है और चूंकि चीन खेलों पर अपने खर्चे के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक ले आता है, तो वह अपने मॉडल को तुलनात्मक रूप से सफल मानता है। चीन ओलंपिक खेलों की मेडल टैली में लगातार अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका को पछाड़ कर नंबर वन होने की कोशिश करता रहा है। चीन ने अपने देश के अंदर बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूलों का मॉडल खड़ा कर रखा है, जिसके जरिए वह अच्छे एथलीट्स तैयार करता है।

भारत में हर बच्चा किसी पॉप स्टार, किसी फिल्म स्टार या किसी अन्य सेलिब्रिटी को अपना आदर्श मानता है। इस सूची में खेलों में सिर्फ क्रिकेट शामिल है, जोकि बेहद महंगा होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय खेल नहीं है। क्रिकेट एशियाई और ओलंपिक में शामिल नहीं है। युवा यदि थोड़ा-बहुत खेलों के प्रति आकर्षित हैं भी तो क्रिकेट की तरफ। ऐसा क्रिकेट में ग्लैमर और पैसा होने के कारण है। ओलंपिक या किसी भी विश्वस्तरीय खेल प्रतियोगिता में भारत को सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और दूरगामी नीति की जरूरत है। भारत में खेलों की स्थिति रातों-रात नहीं बदलेगी। हालांकि, हममें से प्रत्येक द्वारा उठाए गए छोटे-छोटे कदम हमें उस बिंदु तक ले जाएंगे जहां हम अंततः सुधार देखना शुरू कर देंगे। भारत में खेलों की संस्कृति का निर्माण करना और भारत के नवजात खेल परिदृश्य को ऊपर उठाने की जरूरत है। यह जरूरी नहीं है कि हर बच्चा महान खिलाड़ी ही बने। फिर भी यह उनके मन में खेल के बारे में सकारात्मक धारणा बनाने में काफी मददगार साबित होगा।

संपादक की कलम से

बाढ़ और नेता

बाढ़ और नेताजी का चोली-दामन का साथ है। बाढ़ आती है तो नेताजी भी आते हैं। नेताजी आते हैं तो उनके चेले चांटे भी साथ में आते हैं। बाढ़ में चारों तरफ पानी ही पानी होता है। नेताजी भी अपनी आंखों में पानी भर लाते हैं। जिस नेता की आंखों में पानी नहीं आता, वह नेता की श्रेणी में ही नहीं आता। इसलिए नेताजी आंखों में पानी लाने का अभ्यास करते रहते हैं। जहां पानी का स्तर बहुत कम होता है, यानी चुल्लू भर पानी होता है या थोड़ी सूखी जगह होती है, नेताजी वहां सावधानी से पैदल चलते हुए मुआयना करते हैं और फिर फोटो खिंचवाते हैं। फोटो अखबारों में छपती है और चंद चापलूस टाइप के मीडिया वाले यह स्टोरी लिखते हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर नेताजी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और सुख-दुख बांटा। पहले सुख-दुख बंटता है, उसके बाद राहत भी बंटेगी। उसकी अलग से फोटो आएगी। अब जिन इलाकों में नेताजी की सूरत देखे लोगों को मुद्दत बीत गई होती है, वहां के लोग अपने आप को कोसते हैं कि हमारे यहां बाढ़ क्यों नहीं आई। ईश्वर ने बाढ़ के मामले में हमारी उपेक्षा क्यों की। बाढ़ आती तो यकीनन नेताजी भी आते। नेताजी उनके दुख दर्द भी सुनते और फिर नेताजी के साथ-साथ उनके फोटो भी अखबारों में छपते। ईश्वर के पास अगर अखबारें जाती होंगी या ईश्वर स्वर्ग में बैठकर इंडियन चैनल देखते होंगे तो वह यह देखकर खुश हो जाते कि इंडिया में नेताजी कितने संवेदनशील होते हैं। जहां-जहां बाढ़ आती है, वहां वहां वह अवतरित होते हैं। कई बार बाढ़ से पहले से टूटी फूटी सडक़ें और ज्यादा टूट जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि सडक़ पर चल रहे हैं या गड्ढे में चले जाएंगे। डटकर हुए खनन की वजह से बाढ़ के पानी में पुल भी बह जाते हैं। ऐसे में नेताजी की मजबूरी होती है कि हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान में उड़ते हुए बाढ़ प्रभावित इलाके का मुआयना किया जाए। नेताजी हेलीकॉप्टर में खिडक़ी के पास बैठ जाते हैं। जब कैमरामैन पूरी तरह से उनके चेहरे पर कैमरा फोकस कर लेता है तो नेताजी खिडक़ी से नीचे झांककर सर्वेक्षण करने लगते हैं। हेलीकॉप्टर में उनके साथ अधिकारी कम, नेताजी के चेले चंपू ज्यादा होते हैं। चंपू उछल-उछलकर उन्हें बताते हैं कि 'वाह साहब! क्या अद्भुत विहंगम दृश्य है। इस इलाके को अब जल क्रीड़ा की दृष्टि से काफी विकसित किया जा सकता है।' अपनी अपनी समझ के मुताबिक चेले चंपू और भी राय देते हैं। नेताजी धीर गंभीर होकर सुनते रहते हैं क्योंकि कैमरा भी उनके चेहरे पर फोकस होता है और उनके चेहरे के हाव-भाव की वीडियो भी बन रही होती है। वीडियो बनाने वालों को खास हिदायत होती है कि नेताजी का दुख उनके चेहरे पर दिखना चाहिए। उनके चेहरे पर सत्ता का सुकून नहीं दिखना चाहिए। नेताजी चेहरे से जितने गमगीन और दुखी दिखेंगे, पब्लिक में उनकी इमेज की उतनी ही ब्रांडिंग होगी जिसका फायदा चुनावों में मिलेगा। अब यहां कैमरामैन की पूरी टैलेंट दाव पर होती है। उसने सांस रोक कर नेताजी के हाव भाव पकडने होते हैं। नेताजी अगर समाधि में भी बैठे हों तो भी उनके चेहरे की गंभीरता और प्रभु भक्ति में तल्लीन उनकी मुद्रा को चुपचाप कमरे में कैद करना होता है। जरा सा शोर होते ही नेताजी की तंद्रा अगर टूट गई तो समाधि का पूरा खेल चौपट हो जाता है। इसलिए कैमरामैन अत्यंत चौकस रहते हैं। नेताजी भी मुआयना करते हुए कैमरामैन से ज्यादा चौकस रहते हैं। फिर जब जमीनी सर्वेक्षण और हवाई सर्वेक्षण पूरा हो जाता है तो फिर नेताजी राजधानी में लौटकर उच्च स्तरीय बैठक करते हैं। फिर मीडिया से मुखातिब होते हैं। विपक्ष को कोसते हैं कि आपदा की इस घड़ी में भी विपक्ष राजनीति कर रहा है। उनका यह बयान फिर अखबारों में छपता है। पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि राजनीति विपक्ष कर रहा है या नेताजी कर रहे हैं। आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। पब्लिक राहत राशि का इंतजार करती रह जाती है।

गुरमीत बेदी

कविता

हिंसा की जवाबदेही किसकी

देश ने स्वतंत्रता की 78वीं सालगिरह मनाई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक लालकिले पर 11वीं बार 'तिरंगा' फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। वह ऐसे प्रथम गैर-कांग्रेसी एवं भाजपाई प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें देश ने इतना सम्मान दिया है। आज 98 मिनट के प्रधानमंत्री संबोधन का विश्लेषण करने का दिन था। प्रधानमंत्री ने पहली बार देश में 'धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता' पर चर्चा की बात कही है। उस विकृति की ओर भी संकेत किया, जो सर्वनाश का कारण बन सकती है। यह पराकाष्ठा की स्थिति है कि आखिर ऐसी विकृतियां किसकी गोद में पल रही हैं? प्रधानमंत्री के भाषण का फोकस 'विकसित भारत 2047' पर अधिक रहा। उन्होंने महिला अपराधों और अत्याचारों पर भी अपनी पीड़ा व्यक्त की और फांसी की सजा तक का सुझाव दिया। बेशक देश की स्वतंत्रता का मौका था, लिहाजा औसत नागरिक जश्न, उल्लास और आनंद के मूड में था, लेकिन संभ्रांत लोगों के शहर कोलकाता में, आधी रात के आसपास, अचानक एक भीड़ उमड़ आई। सैकड़ों होंगे अथवा हजारों होंगे, यह गणना बेमानी है।

वे गुंडे-बदमाश, हिंसक और विध्वंसक थे। उनके हाथों में लाठियां, डंडे थे और वे काफी उग्रलग रहे थे। स्वतंत्रता की पूर्व रात्रि में भारतीय ही भारतीय पर हमलावर होगा, ऐसी आजादी की हमने कल्पना तक नहीं की थी। क्या हमें ऐसी ही आजादी चाहिए? भीड़ ने पहला हमला प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर किया। उन्हें तितर-बितर किया। मारा-पीटा, तोड़-फोड़ की और प्रदर्शन का मंच ही ध्वस्त कर दिया। उसके बाद भीड़ उस सरकारी अस्पताल के अंदर घुस गई, जहां कुछ दिनों पहले ही 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बर बलात्कार किया गया और बाद में दरिंदगी से उसकी हत्या भी कर दी गई थी। अस्पताल के भीतर भी खूब तोड़-फोड़ की। आपातकालीन कक्ष और बिस्तरों को भी नहीं छोड़ा। गंभीर चिकित्सा विभाग को भी अस्त-व्यस्त कर दिया। संभव है कि उस जघन्य, वहशियाना अपराध के कुछ सबूत भी मिटा दिए गए हों! आखिर वह भीड़ कहां से आई? कौन थे वे गुंडे और उनकी मंशा क्या थी? भीड़ की अराजकता से, अंततः, किसे लाभ हो सकता है? बंगाल पुलिस कहां थी? यदि ठुल्ले तैनात थे, तो वे तमाशबीन ही क्यों बने रहे? पुलिस और भीड़ में कोई सांठगांठ थी क्या? क्या सीबीआई जांच भी प्रभावित होगी? बहरहाल इन सवालों के जवाबों की प्रतीक्षा प्रधानमंत्री मोदी को नहीं करनी चाहिए। उन्हें राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ताजा रपट मंगवानी चाहिए और केंद्रीय कैबिनेट को अनुच्छेद 356 के तहत पश्चिम बंगाल में 'राष्ट्रपति शासन' चस्पा कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिल्लाने और संघीय ढांचे की दुहाई देने दो।

दरअसल यह भीड़ और यह मार-काट बंगाल की नई परंपरा, नया रूटीन बन गई है। कभी संदेशखाली में, तो कभी 24 परगना अथवा किसी अन्य क्षेत्र में भीड़ हिंसा पर उतारू उमड़ती है। हत्याएं तक करना आम बात है। ममता बनर्जी 2011 से मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री हैं, लिहाजा कानून-व्यवस्था की बुनियादी जिम्मेदारी उन्हीं की है। क्या देश की स्वतंत्रता के दिन भी ऐसी उन्मादी, उग्र भीड़ तोड़-फोड़, मार-काट करने को स्वतंत्र है? देश की महिलाएं, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री से, पूछ रही हैं कि आखिर ममता किसकी 'दीदी' हैं? बेशक ममता अब धरने पर बैठ राजनीति करें, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि राम और वाम इक_ा हो गए हैं और अशांति फैला रहे हैं। 'राम' नाम का इस तरह प्रयोग घोर आपत्तिजनक है। बहरहाल भीड़ डॉक्टरों को हतोत्साहित नहीं कर पाई है, क्योंकि जो डॉक्टर काम पर लौट गए थे, वे फिर हड़ताल पर वापस चले गए हैं। भारत में डॉक्टरों की

रमेश धवाला

नशे की बढ़ती लत से समाज खतरे में

समय की जरूरत है कि सरकार नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़े कानून बनाए। शिक्षण संस्थानों में 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू-गुटखा बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एनजीओ, धार्मिक संगठनों, सिविल सोसाइटीज, पंचायतों, शहरी निकायों, स्टूडेंट्स यूनियनों, यूथ क्लबों, नेहरु युवा क्लबों, शिक्षकों को तन-मन-धन से नशे के खिलाफ सहयोग करना चाहिए। जब स्टूडेंट्स कॉलेज-यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उनको नशे के खिलाफ वर्कशॉप और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए'

समाज के बदलते परिवेश में कुछ अलग करने की कामना, मानसिक तनाव और बहुत से शौक ऐसे कारण हैं जो नशे के प्रचलन को समाज में बढ़ा रहे हैं। इसका ज्यादातर शिकार हमारी युवा पीढ़ी हो रही है। वर्तमान में नशा युवाओं के लिए फैशन बन गया है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नशे का हानिकारक प्रभाव न केवल नशा करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, अपितु यह पूरे परिवार और समाज को भी खोखला करने का काम करता है। एक समय हिमाचल को बदनाम करने वाले भांग, अफीम और चरस जैसे खतरनाक नशे की जगह अब चिट्टे ने ले ली है। चिट्टा वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक ड्रग्स है। हिमाचल का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां पर पुलिस द्वारा चिट्टे की बरामदगी न हुई हो, खासकर सीमांत जिलों कांगड़ा, ऊना एवं सोलन जैसे जिलों में चिट्टे का सर्वाधिक प्रकोप है, जो कि कई युवाओं के जीवन को निगल चुका है। अक्सर नशेड़ी आदमी को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फिर भी न चाहते हुए भी वे इस लत से छुटकारा नहीं पा सकते। वर्तमान में हालात ऐसे बन चुके हैं कि स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटीज में पढने वाले विद्यार्थी नशाखोरी की चपेट में आने लगे हैं। नशा माफिया छात्रों को किसी तरह से बहला-फुसला कर नशे की लत लगा देता है और जब ये छात्र इस महंगे नशे को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं तो नशा माफिया इन बच्चों को नशा तस्करी के दलदल में धकेल देता है। अभी कुछ समय पहले ही एनआईटी हमीरपुर में कई छात्र इस नशाखोरी के चक्कर में पकड़े गए थे। आजकल आधुनिकता की दौड़ में संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार को तरजीह दी जा रही है। ऐसे में बच्चों में अकेलापन, सामाजिकता का अभाव इत्यादि के कारण बच्चों में नशे की तरफ रुचि बढ़ जाती है। अगर एकल परिवार का लडक़ा या लडक़ी नशे के जाल में फंसते हैं तो उस परिवार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। अक्सर देखने में आता है कि नशे में पड़ा छात्र झूठ बोलने लगता है एवं अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज को धोखा देने लगता है। नशे के लिए पैसे का जुगाड़ करने के लिए चोरी, डकैती, अपने ही घर का सामान बेचना जैसी खबरें हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं। एक बार सिंथेटिक ड्रग्स की लत लग जाए तो इस नशे को छोड़ पाना इतना आसान नहीं होता।

इसकी लत इतनी खतरनाक होती है कि अगर व्यक्ति को नशा न मिले तो यह नशेड़ी की मौत का कारण बन जाता है। आज जरूरत है समाज में इस दानव रूपी नशे के कारोबार को खत्म किया जाए। सरकारें भी इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है। माता-पिता अपने बच्चों की परवरिश करते समय अगर बच्चे की छोटी-मोटी गतिविधियों पर नजर नहीं रखेंगे तो बच्चे गलत संगत में पड़ कर नशे का शिकार बन सकते हैं। कई बार अपनी विधानसभा या हिमाचल के किसी और क्षेत्र में जाता हूं तो स्कूल-कॉलेज के छात्र सिरगेट के धुएं के छल्ले उड़ाते दिखते हैं, तो मन में पीड़ा होती है। कई बार गाड़ी रोककर ऐसे बच्चों को समझाने का भी प्रयास करता हूं। समय की जरूरत है कि सरकार नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़े कानून बनाए। शिक्षण संस्थानों में 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू-गुटखा बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एनजीओ, धार्मिक संगठनों, सिविल सोसाइटीज, पंचायतों, शहरी निकायों, स्टूडेंट्स यूनियनों, यूथ क्लबों, नेहरु युवा क्लबों, शिक्षकों को तन-मन-धन से नशे के खिलाफ सहयोग करना चाहिए। जब स्टूडेंट्स कॉलेज-यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उनको नशे के खिलाफ वर्कशॉप और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। सरकारों को युवाओं के लिए अवसर, खेलों एवं रोजगार की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि युवा अपनी एनर्जी और क्रिएटिव पावर्स का समाज और देशहित में प्रयोग कर सकें। पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है। पंजाब अब उड़ता पंजाब कहलाता है। वहां पर नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण वह अब खेलों में भी पीछे हो गया है।

वास्तव में जरूरत इस बात की है कि जब बच्चे अपनी किशोरावस्था में हों तो उन पर माता-पिता को कड़ी नजर रखनी चाहिए। इसी अवस्था में बच्चों के फिसल जाने की आशंका बहुत होती है। जब बच्चे युवा हो जाते हैं, तब तक वे समझदार बन चुके होते हैं, उस अवस्था में नशे की ओर वे नहीं बढ़ते। युवाओं का मानस खेलों की ओर मोडऩा चाहिए। खेलों से वे अपने समय का सदुपयोग ठीक ढंग से कर पाएंगे, नशे से भी दूर रहेंगे और अपना शारीरिक-मानसिक विकास भी कर पाएंगे। नशा ऐसी बुरी आदत होती है जो अपने साथ कई अपराध लेकर आती है। जब नशेडियों को नशा नहीं मिलता तो वे चोरी-डकैती की ओर बढ़ते हैं। इससे समाज में असामाजिक तत्वों की संख्या बढने लगती है और समाज में तनाव तथा अशांति का माहौल बनने लगता है। ऐसा भी माना जाता है कि पूरे विश्व में इतने लोग युद्धों में नहीं मरते, जितने नशे के कारण मर जाते हैं। युवा पीढ़ी में शराब, गुटखा, स्मोकिंग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक तथा कई अन्य नशीले पदार्थों का बढ़ता प्रचलन समाज को एक खतरनाक दिशा की ओर ले जा रहा है। इस विषय में तुरंत जागरूक होने की जरूरत है।

आर्थिक डेस्टिनेशन-1

हिमाचल अपने होने की बुलंदी में, नए युग से आंखें चार कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सरकार का हर पांव आर्थिक डेस्टिनेशन खोज रहा है। इरादे अपने नैन-नक्श नहीं बताते, मगर ताकत का इजहार जरूर करते हैं। हम सुखविंदर सिंह सरकार को राजनीतिक पैमानों में देखें या प्रदेश के आर्थिक हालात में महसूस करें, लेकिन सच यह है कि प्रदेश को तकदीर सत्ता से नहीं मिलती-सरकार के इरादों से हासिल होती है। कोशिश के स्तंभ खड़े करते मुख्यमंत्री ने कम से कम हिमाचल के प्रगतिशील आईने तो देख लिए हैं। सरकार पर्यटन उद्योग पर पूर्ण भरोसा कर रही है। इससे पहले जयराम सरकार ने निजी निवेश, तो प्रेम कुमार धूमल ने हाइड्रो पावर में जोर आजमाया। शिमला में विभागीय समीक्षा बैठकों के सिलसिले में मुख्यमंत्री सुक्खू ने पर्यटन और ग्रामीण आर्थिकी के द्वार खोले हैं। उनके प्रयास पर्यटन की खूबियों में इंगित हैं, तथा वह उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को आजमाना चाहते हैं, जहां जीएसटी का सीधा लाभ राज्य की माली हालत को सुदृढ़ करे। सरकार का खाका बताता है कि इस बार पर्यटन की बुलंदी के लिए कांगड़ा को 'टूरिज्म कैपिटल' बनाया जाएगा। अगर यह राजनीतिक नारा या प्राथमिकता न बने, तो पौंग झील, ब्यास नदी, चाय बागान व धौलाधार पर आकर पर्यटन का आसमान स्पष्ट दिखाई देगा। इससे पूर्व शांता कुमार जब केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने धौलाधार पर्यटन परियोजना के तहत करीब पांच सौ करोड़ की रूपरेखा बनाई थी। प्रो. चंद्र कुमार जब सांसद थे, तो पौंग गलियारे की पर्यटक योजना के लिए 1800 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया था। हकीकत इससे भिन्न रही, क्योंकि पर्यटन की क्षमता का मूल्यांकन नहीं हुआ और कई परियोजनाओं में पैसा जाया हो गया। कांगड़ा के नूरपुर व पौंग बांध के छोर पर बने तीन पर्यटन यूनिट जीरो साबित हो गए।

बैजनाथ, कोटला, वार मेमोरियल व भागसूनाग के कैफे बिना किसी कारण बेच दिए गए। आज तक हम पौंग डैम में आते प्रवासी पक्षियों की शुमारी में पर्यटन नहीं खोज पाए। प्राचीन धरोहरों से समृद्ध हरिपुर-गुलेर, पुराना कांगड़ा, चैतड़ू, नादौन, सुजानपुर टीहरा व मसरूर को पर्यटन की मुख्यधारा से नहीं जोड़ पाए। कांगड़ा के बजाय धौलाधार तथा ब्यास नदी पर्यटक कैपिटल कहें तो संदर्भ व्यापक होते हैं, तब होली-उत्तराला, चुबाड़ी-चंबा तथा हिमानी चामुंडा-होली सुरंग परियोजनाओं की परिकल्पना में कितनी ही नई पर्यटन राजधानियां जन्म लेंगी। एक छोटे से प्रयास से शुरू हुआ बीड़-बिलिंग का सफर आज अगर दुनिया के नक्शे पर पैराग्लाइडिंग की सर्वश्रेष्ठ साइट बन गया, तो ऐसे कई दरवाजे खुल सकते हैं। गरली-परागपुर को अगर हिमाचल की प्रथम फिल्म सिटी बना दें, तो ये धरोहर गांव कांगड़ा के अलावा चंबा, मंडी, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में फिल्म शूटिंग के जरिए सिने पर्यटन का नया नक्शा बना सकते हैं। पर्यटन को भीड़ बनने से नहीं बचाया तो हमारे ख्वाब भटक जाएंगे। मसलन बरसात में पर्यटन नहीं पर्यटन के मेंढक टर्राते हैं। आजकल हिमाचल की सडक़ों पर उतरे दोपहिया वाहनों में कदापि पर्यटन अपना भ्रमण नहीं कर रहा, बल्कि इस सैर सपाटे ने हिमाचल का हुलिया और पुलिस व्यवस्था की गरिमा बिगाड़ दी है। मंडी में इसी तरह की हुल्लड़बाजी में अगर तथाकथित पर्यटक बंदूक तान रहे हैं, तो पांच करोड़ सैलानियों की आमद से पहले कम से कम पांच लाख की संख्या में पर्यटक पुलिस के जवान तैनात करने पड़ेंगे। हिमाचल को त्वरित प्रभाव से तमाम पर्यटक स्थलों पर ग्रीन टैक्स लगा देना चाहिए। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए तमाम धार्मिक स्थलों में क्षमता विस्तार के अलावा प्रमुख स्थलों पर नई इमारतों के बजाय खुले स्थल, पार्क, मनोरंजन पार्क, महापार्किंग स्थल, नए बाजार, नए बस स्टैंड, साइट सीईंग पैकेज तथा तिब्बती एवं बौद्ध सर्किट का विकास करना होगा। धर्मशाला और मनाली के बीच जोगिंद्रनगर के आसपास काल चक्र सम्मेलन स्थल विकसित करें, तो महामहिम दलाईलामा के प्रवचनों से जुड़ा पर्यटन इसे वैश्विक आधार देगा।

2027 तक तीसरी बड़ी आर्थिकी बन जाएगा भारत, IMF के साथ सहयोग बढ़ाने की तैयारी- निर्मला सीतारमण

परिवहन विशेष न्यूज

वित्त मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में बताया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आइएमएफ के साथ अपने संबंधों और निरंतर सहभागिता को अत्यधिक महत्व देता है। भविष्य को देखते हुए भारत सरकार आइएमएफ के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए और अधिक तरीके तलाशने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने गीता गोपीनाथ से मिलने के बाद ये कहा है।

नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आइएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ से मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत आइएमएफ के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए और अधिक तरीके तलाशने को तैयार है। मुलाकात के दौरान गोपीनाथ ने राजकोषीय समेकन में नीतिगत निरंतरता के लिए वित्त मंत्री को बधाई भी दी। वित्त मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में बताया, 'वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आइएमएफ के साथ अपने संबंधों और निरंतर सहभागिता को अत्यधिक महत्व देता है। भविष्य को देखते हुए भारत सरकार आइएमएफ के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए और अधिक तरीके तलाशने के लिए तैयार है।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि भारत सभी क्षेत्रों में बड़े सुधार कर रहा है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी पीएम के इस दावे का समर्थन किया है। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अभी दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दमदार विकास दर की बदौलत जल्द ही सबसे आगे निकल सकता है। गीता गोपीनाथ का कहना है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर रही है।

इसका कारण सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी होना रहा है। खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी खपत बढ़ी है। साथ ही, दोपहिया की बिक्री से लेकर एफएमसीजी क्षेत्र तक सभी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। मौसम विभाग ने इस साल मानसून सामान्य रहने का अनुमान जताया है। गीता गोपीनाथ ने कहा कि बेहतर मानसून के साथ उपज भी बेहतर होती है और कृषि आय बढ़ती है। इससे आगे भी खपत बढ़ने का सिलसिला जारी रह सकता है। सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) के ताजा डाटा के अनुसार, जुलाई में यात्री वाहनों, तिपहिया, दोपहिया और क्वाड्रिसाइकिल का कुल उत्पादन 24,37,138 यूनिट रहा है।

दूसरी ओर, तमाम चुनौतियों के बावजूद एफएमसीजी बाजार लचीला बना हुआ है। रिसर्च फार्म कांतार के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण बाजार में एफएमसीजी क्षेत्र की वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रह सकती है जो पिछले वित्त वर्ष में 4.4 प्रतिशत थी।

अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने की जरूरत

आइएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि भारत को अगले 5-6 वर्षों में लाखों अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने की जरूरत है। आइएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है। हाल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि अगर तीन वर्षों में भारत की औसत वृद्धि को देखा जाए तो यह 8.3 प्रतिशत होती है। RBI ने चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

भारत कब बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, IMF की गीता गोपीनाथ ने बताया

परिवहन विशेष न्यूज

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. गीता गोपीनाथ का कहना है कि भारत अगले तीन साल यानी 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अभी दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हालांकि गीता गोपीनाथ का कहना है कि अतिरिक्त रोजगार पैदा करना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है।

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन में कहा था कि भारत सभी क्षेत्रों बड़े सुधार कर रहा है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। अब पीएम मोदी के दावे पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी अपनी मुहर लगा दी है।

आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर गीता गोपीनाथ का कहना है कि भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

अभी पांचवें नंबर पर भारत

भारत अभी पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन दमदार विकास दर की बदौलत वह जल्द ही सबसे आगे निकल सकता है। गीता गोपीनाथ के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही, क्योंकि सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी दिखी। खासकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी खपत बढ़ी है। साथ ही, दोपहिया गाड़ियों की बिक्री से लेकर FMCG सेक्टर तक सभी काबिलेतारीफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

बेहतर मानसून से और बढ़ेगी खपत

मौसम विभाग ने इस साल मानसून सामान्य रहने का अनुमान जताया है। गीता गोपीनाथ ने कहा, 'बेहतर मानसून के साथ उपज भी बेहतर होती है और कृषि आय बढ़ती है। इससे आगे भी खपत बढ़ने का सिलसिला जारी रह सकता है।₹ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, जुलाई में यात्री वाहनों, तिपहिया, दोपहिया और क्वाड्रिसाइकिल का कुल उत्पादन 24,37,138 यूनिट तक पहुंच गया। भारत में FMCG बाजार तमाम चुनौतियों के बावजूद लचीला बना हुआ है।

रोजगार के मोर्चे पर रहेगी चुनौती

गीता गोपीनाथ का कहना है कि भारत को अगले 5-6 वर्षों में लाखों अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने की जरूरत है।

बिल गेट्स ने भी हिंदुस्तानियों का माना लोहा, कहा- इनोवेशन में भारत का कोई तोड़ नहीं

बिल गेट्स ने टेक्नोलॉजी के साथ कृषि और स्वास्थ्य सेवा में तरक्की के लिए भारत की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि इन नवाचारों से लोगों की जिंदगी बेहतर करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स ने कार्यक्रम में तिरंगे के रंग का दुपट्टा पहन रखा था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की और समारोह में हिस्सा लेने को सम्मान की बात बताया।

माइक्रोसॉफ्ट को-फाउंडर और मशहूर परोपकारी बिल गेट्स ने अमेरिका के ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में पहली बार भारत दिवस समारोह की शुरुआत की और भारत को अलग-अलग क्षेत्रों में अभूतपूर्व नवाचारों वाला 'ग्लोबल लीडर₹ बताया। उन्हें भारत के महावाणिज्य दूतावास ने बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था। गेट्स ने टेक्नोलॉजी के साथ कृषि और स्वास्थ्य सेवा में तरक्की के लिए भारत की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि इन नवाचारों से लोगों की जिंदगी बेहतर करने में मदद मिलेगी।

तिरंगे का दुपट्टा पहने थे बिल गेट्स

अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स ने कार्यक्रम में भारतीय तिरंगे के रंग का दुपट्टा पहन रखा था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की और समारोह में हिस्सा लेने को सम्मान की बात बताया। गेट्स ने लिखा, ₹भारत प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व नवाचारों वाला वैश्विक नेता है, जो जीवन को बचा रहा है और बेहतर बना रहा है। भारत सरकार परोपकारी लोगों, निजी क्षेत्र, गैर-लाभकारी संस्थाओं और भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ सहयोग करना सम्मान की बात है। सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!"

दूतावास ने गेट्स को शुक्रिया कहा

वहीं, सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए गेट्स का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, ₹ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में पहले भारत दिवस समारोह को हरी झंडी दिखाने के लिए बिल गेट्स को धन्यवाद।₹ वाणिज्य दूतावास ने कांग्रेस की महिला सदस्य सुजान के डेलबेने और किम श्रियर, कांग्रेसी एडम स्मिथ, वाशिंगटन के लेफ्टिनेंट गवर्नर डेनी हेक और वाशिंगटन के राज्य सचिव स्टीव हॉब्स की भागीदारी को भी स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, बेलेव्यू, टैकोमा, केंट, ऑबर्न, रेंटन, सीटैक, स्नोक्वाल्मी और मर्सर आइलैंड सहित कई निकटवर्ती शहरों के महापौरों ने समारोह में भाग लिया और भारतीय समुदाय के प्रति अपना समर्थन दिखाया।

वित्तीय तनाव से गुजर रहे ब्लू-कॉलर जॉब करने वाले, ज्यादातर का वेतन 20 हजार से भी कम

वर्कइंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 57 .63 प्रतिशत से अधिक ब्लू-कॉलर जॉब वाले लोग हर महीने 20000 रुपये या इससे भी कम कमाते हैं। यह रकम देश में न्यूनतम वेतन सीमा के करीब है। वहीं करीब 29 .34 प्रतिशत ब्लू-कॉलर जॉब वाले मिडल इनकम कैटेगरी में हैं। उनका वेतन 20 से 40 हजार रुपये के बीच है। सिर्फ 10 .71 फीसदी लोगों को 40 से 60 हजार रुपये महीना का वेतन मिलता है।

नई दिल्ली। भारत में अधिकतर ब्लू-कॉलर जॉब में तनख्वाह 20 हजार रुपये या इससे भी कम है। यह तबका वित्तीय तनाव से गुजर रहा है। उसे आवास, चिकित्सा और शिक्षा जैसी जरूरतों को पूरा करने में भारी मुश्किल हो रही है। यह जानकारी ब्लू कॉलर भर्ती प्लेटफॉर्म वर्कइंडिया के एक रिपोर्ट से मिली है।

क्या होती है ब्लू कॉलर जॉब?

नौकरियां अमूमन दो तरह की होती हैं, व्हाइट-कॉलर और ब्लू-कॉलर। व्हाइट-कॉलर में दफ्तरों में काम करने वाले पेशेवर लोग आते हैं, जिन्हें शारीरिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं, ब्लू कॉलर में शारीरिक तौर पर अधिक मेहनत करने वाले लोग आते हैं, जिन्हें अपेक्षाकृत कम तनख्वाह मिलती है। जैसे कि वेल्डर, मैकेनिक, किसान, रसोइया, ड्राइवर आदि।

क्या कहती है वर्कइंडिया रिपोर्ट?

वर्कइंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 57.63 प्रतिशत से अधिक ब्लू-कॉलर जॉब वाले लोग हर महीने 20,000 रुपये या इससे भी कम कमाते हैं। यह रकम देश में न्यूनतम वेतन सीमा के करीब है। वहीं, करीब 29.34 प्रतिशत ब्लू-कॉलर जॉब वाले मिडल इनकम कैटेगरी में हैं। उनका वेतन 20 से 40 हजार रुपये के बीच है। इस कमाई में जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन बचत या फिर निवेश के लिए गुंजाइश काफी कम बचती है।

अच्छे वेतन के अवसर सीमित

वर्कइंडिया के सीईओ और कोफ-फाउंजर नीलेश डूंगरवाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, 'हमारे डेटा से पता चलता है कि ब्लू-कॉलर सेक्टर में कम वेतन वाली नौकरियों की संख्या ज्यादा है। वहीं, ज्यादा कमाई के अवसर सीमित हैं। इससे वर्कफोर्स के एक बड़े हिस्से की चुनौतियों का पता चलता है। सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए भी इसके गहरे मायने हैं।'

सिर्फ 10% को अच्छा वेतन

रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ 10.71 फीसदी लोगों को 40 से 60 हजार रुपये प्रति महीना का वेतन मिलता है। इनके पास कोई विशेष हुनर या फिर अनुभव है। इस तरह के पदों की उपलब्धता भी सीमित है। यहां तक पहुंचने या फिर इससे ऊपर जाने में लोगों को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

कैसे दूर होगी समस्या?

वर्कइंडिया के को-फाउंडर डूंगरवाल का कहना है कि श्रमिकों के बड़े हिस्से की दिक्कतों को दूर करने के लिए सामूहिक तौर पर प्रयास करना होगा। उनके हुनर को तराशना होगा, वेतन बढ़ाना होगा, साथ ही अधिक वेतन वाली नौकरियों के ज्यादा अवसर पैदा करने होंगे। बजट में भी केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया है।

रक्षाबंधन पर बहन को दें सुनहरे भविष्य का तोहफा, शेयर से लेकर SIP तक हैं कई विकल्प

देशभर में सोमवार (19 अगस्त) को राखी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी खुशहाली और समृद्धि की दुआ मांगती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। कई बार ये उपहार नकद पैसे या फिर जेवरात के रूप में होते हैं। लेकिन बहन को कुछ ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं जिसका उनका आर्थिक भविष्य बेहतर हो।

नई दिल्ली। गुरुग्राम की रहने वाली नेहा को उनके अंकल से बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक कंपनी के 400 शेयर मिले थे। एक शेयर की कीमत 18 रुपये थी यानी कुल 7,200 रुपये के शेयर। उस कंपनी का नाम है SRF लिमिटेड और आज उसके एक शेयर का भाव है करीब 2,500 रुपये। इसका मतलब कि 7,200 रुपये के गिफ्ट की कीमत आज तकरीबन 10 लाख रुपये है।

रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर भाई अक्सर बहन को बड़े प्यार से तमाम उपहार देते हैं। इनमें नकद पैसों से लेकर गहने तक शामिल होते हैं। लेकिन, अगर आप बहन का आर्थिक भविष्य बेहतर करना चाहते हैं, तो उसे शेयर या फिर SIP जैसे वित्तीय उपहार दे सकते हैं। इससे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा और उनकी वित्तीय जरूरतें पूरा होंगी।

स्टॉक्स का दे सकते हैं तोहफा

आप अपनी बहन का डीमैट अकाउंट खुलवाकर उन्हें स्टॉक्स का गिफ्ट दे सकते हैं। हालांकि, आप आपको अच्छे फंडामेंटल्स वाले शेयर गिफ्ट करने चाहिए, जिनमें कम जोखिम रहे। आप मिड या फिर लॉर्ज कैप शेयरों पर विचार कर सकते हैं, जो अपने सेक्टर में अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं।

म्यूचुअल फंड भी अच्छा विकल्प

आप रक्षाबंधन पर म्यूचुअल फंड (Mutual fund) का तोहफा भी दे सकते हैं। इस सूरत में एकमुश्त निवेश वाला म्यूचुअल फंड प्लान चुन सकते हैं। अगर आपकी बहन खुद भी आगे निवेश की इच्छुक हैं, तो उन्हें SIP वाला प्लान दे सकते हैं। लॉर्ज और मिड कैप सुझाना बेहतर रहेगा, क्योंकि इनमें जोखिम कम रहता है।

एफडी रहेगी सबसे सेफ ऑप्शन

अगर आप या आपकी बहन शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचना चाहते हैं, तो बैंक एफडी का गिफ्ट भी चुना जा सकता है। इसमें पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, साथ ही एक रिटर्न भी मिलता है। आप किसी भी बैंक या NBFC में बहन के नाम की एफडी खुलवा सकते हैं, जिसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो।

अगस्त में विदेशी निवेशकों की इक्विटी बाजारों से निकासी जारी

एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक इक्विटी बाजारों में एफपीआई का कुल निवेश घटकर 14365 करोड़ रुपये रह गया है। हालांकि घरेलू डेट या बॉन्ड बाजारों में एफपीआई निवेश जारी है। 16 अगस्त तक एफपीआई डेट बाजारों में 9112 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। इसके साथ ही डेट बाजारों में एफपीआई का कुल निवेश एक लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है।

नई दिल्ली। अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की इक्विटी बाजारों से निकासी जारी है। नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डाटा के अनुसार, 16 अगस्त तक एफपीआई इक्विटी बाजारों से 21,201 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं। इससे पहले जुलाई और जून में एफपीआई ने इक्विटी में क्रमशः 32,365 करोड़ और 26,565 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था।

एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक इक्विटी बाजारों में एफपीआई का कुल निवेश घटकर 14,365 करोड़ रुपये रह गया है। हालांकि, घरेलू डेट या बॉन्ड बाजारों में एफपीआई निवेश जारी है। 16 अगस्त तक एफपीआई डेट बाजारों में 9,112 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। इसके साथ ही डेट बाजारों में एफपीआई का कुल निवेश एक लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है। एफपीआई ने इससे पहले जुलाई में डेट बाजारों में 22,363 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

डेट बाजारों में एफपीआई के आकर्षण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 में अब तक केवल एक महीने यानी अप्रैल में निकासी की गई है। अन्य सभी महीनों में एफपीआई डेट बाजारों में शुद्ध रूप से निवेशक रहे हैं। वाटरफील्ड एडवाइजर्स के विपुल भोवार का कहना है कि घरेलू बाजारों में बीती कुछ तिमाहियों में जबरदस्त तेजी के बाद कुछ एफपीआई मुनाफा वसूली कर रहे हैं। साथ ही ज्यादा मूल्यांकन के कारण भारतीय शेयर बाजार कम आकर्षक हो गए हैं।

क्या है पीसी अधिनियम की धारा 17A ? जिसके तहत राज्यपाल ने दी कर्नाटक CM के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुडा भूखंड आवंटन घोटाले में प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत दी गई है। बता दें कि सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की खातिर राज्यपाल से मंजूरी लेना अनिवार्य है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच और मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुडा भूखंड आवंटन घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए शनिवार को इसी अधिकार के तहत मंजूरी दी।

कर्नाटक के राज्यपाल सचिवालय ने कथित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 218 के तहत सिद्दरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग को स्वीकार किया। कानून के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं और कानूनी स्थिति के मद्देनजर आरोपित को पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य

एक संशोधन के माध्यम से 2018 में शामिल की गई पीसी अधिनियम की धारा 17ए के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ पूछताछ या जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है यानी प्रविधान कहता है कि एक पुलिस अधिकारी को ऐसे अपराधों की जांच करने से पहले पूर्वानुमति लेनी होगी। सक्षम प्राधिकारी को जांच एजेंसी से अनुरोध प्राप्त होने के 120 दिन के भीतर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेना होगा।

बीएनएसएस की धारा 218 लागू

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकसेवकों को परेशान न किया जाए। इसने यह भी कहा है कि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता पूर्ण नहीं है और वास्तविक आरोपों की अदालत को पड़ताल करने की अनुमति होनी चाहिए। कर्नाटक के राज्यपाल ने बीएनएसएस की धारा 218 भी लागू की है, जिसने हाल ही में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह ली है।

डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से मरीज हुए परेशान, पटना में 200 ऑपरेशन टले; बेतिया में बिना इलाज 1500 लोग लौटे

डॉक्टरों की हड़ताल का राष्ट्रव्यापी असर शनिवार को देखने को मिला। कई राज्यों में मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा। वहीं सैकड़ों ऑपरेशन को टालना पड़ा। झारखंड में 17 हजार चिकित्सकों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में आठ दिन से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अब शनिवार को वरिष्ठ चिकित्सक भी इसमें शामिल हो गए हैं।

नईदिल्ली। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के विरोध में शनिवार को देशभर में चिकित्सक हड़ताल पर रहे। सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी और कारपोरेट अस्पताल और नर्सिंग होम के भी हड़ताल में शामिल होने से स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गईं।

हड़ताल में शामिल हुए इन राज्यों के डॉक्टर

बड़े अस्पतालों में भी ऑपरेशन टाल दिए गए। हड़ताल के कारण मरीजों और उनके साथ आए तिमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के आह्वान पर राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मिजोरम और नगालैंड सहित विभिन्न राज्यों के डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल में शामिल हुए।

बंगाल में आठ दिन से हड़ताल

दिल्ली में सर गंगा राम, फोर्टिस और अपोलो जैसे अस्पतालों ने अपनी ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी और आइपीडी सेवाएं बंद कर रखीं। बंगाल में जूनियर डॉक्टर आठ दिन से हड़ताल पर हैं। शनिवार को वरिष्ठ चिकित्सक भी शामिल हो गए। सरकारी अस्पतालों में गैर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं। निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में भी कमोबेश यही हालात रहे।

पटना में 200 ऑपरेशन टले

बिहार में पटना के सभी प्रमुख अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रही। प्रमुख अस्पतालों में 200 से अधिक ऑपरेशन टल गए। दरभंगा के डीएमसीएच में दो दिनों में आठ ऑपरेशन टाले गए गए हैं। मुजफ्फरपुर में निजी व सरकारी अस्पतालों में ताला लटका रहा। राजकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बेतिया से 1500 मरीज लौट गए। भागलपुर में जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल में ओपीडी सेवा बंद रही। करीब 1500 मरीज बिना उपचार के लौट गए।

पीएम मोदी से मिले चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के लिए मांगी सहायता

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय बजट के बाद मोदी के साथ अपनी पहली बैठक में नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इसमें नई राजधानी के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की फंडिंग भी शामिल है।

नईदिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर कर्ज में डूबे अपने राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय बजट के बाद मोदी के साथ अपनी पहली बैठक में नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इसमें नई राजधानी के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की फंडिंग भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राजकोषीय चुनौतियों से निपटने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और राज्य की जीडीपी बढ़ाने के लिए केंद्रीय समर्थन का अनुरोध किया।

सीतारमण से मुलाकात की

बाद में नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपने राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उनके गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने की संभावना है। तेदेपा अपने 16 लोकसभा सदस्यों के साथ केंद्र में राजग सरकार का एक प्रमुख घटक है।

आज से 2 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर: आज से 2 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है । प्रशिक्षण कार्यक्रम आज और कल दो दिनों तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया । इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सूरमा पाढ़ी, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, दो उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिडा शामिल हुए हैं।वहीं दूसरी ओर बीजेडी और कांग्रेस विधायकों ने ट्रेनीग कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है । बिजुडी% सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, सदन की गरिमा को नष्ट होने की बात कहते हुए विपक्ष की मुख्य सचिव प्रमिला मल्लिक ने पहले ही स्पीकर को पत्र लिखा है । वहीं, कांग्रेस ने भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है । वहीं संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा, इस बार 87 नए विधायक चुने गए हैं। परंपरागत रूप से, नए विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह उसी क्रम में आयोजित किया जाता है।

श्री आईजी गौशाला में स्वतंत्र दिवस मनाया

परिवहन विशेष न्यूज

बालाजी नगर स्थित श्री आईजी गौशाला में स्वतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आयोजित ध्वजा रोहण कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष मंगलाराम पंवार,सचिव हुक्माराम सानपुरा, कालुराम काग चितल, भगाराम मुलेवा, भंवरलाल मुलेवा,पवन गेहलोत, मांगीलाल किसरा किशनलाल पंवार,माधुराम चोयल, मोहनलाल हाम्बड़, प्रकाश चोयल,पुखराम मुलेवा, मांगीलाल काग, मुकेश, व महिला मण्डली एवं अन्य उपस्थित रहे।

22 अगस्त को होगी JPC की पहली बैठक, वक्फ संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा

वक्फ अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी। यह बैठक दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि जेपीसी के सदस्यों को विधेयक के बारे में जानकारी देंगे। बता दें कि जेपीसी में कुल 31 सदस्य हैं। इनमें से 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद हैं।

नई दिल्ली। वक्फ बोर्ड में सुधार से जुड़े विधेयक पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक अगले सप्ताह होगी। लोकसभा सचिवालय के नोटिस में कहा गया है कि भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति 22 अगस्त को अल्पसंख्यक मामलों और विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी।

बैठक के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि सदस्यों को विधेयक और विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी देंगे। जेपीसी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं। समिति को संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। यह विधेयक भाजपा के नेतृत्व

वाली राजग सरकार की पहली बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार लाना है।

कई सुधारों का प्रस्ताव

इसमें कई सुधारों का प्रस्ताव है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य वक्फ बोर्डों के साथ केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना भी शामिल है। इस विधेयक को आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। बहस के बाद विधेयक को जेपीसी को सौंपने का फैसला लिया गया।

विपक्ष ने किया विधेयक का विरोध

विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया था और इसे संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला करार दिया, वहीं अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि विधेयक में किसी की धार्मिक स्वतंत्रता तथा संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है।

मनु सिंघवी कांग्रेस के विधि विभाग के अध्यक्ष नियुक्त, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए वार-रूम अध्यक्षों की हुई नियुक्ति

कांग्रेस ने शनिवार को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अपने विधि मानवाधिकार और आरटीआइ विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से विधि मानवाधिकार और आरटीआइ विभाग के पुनर्गठन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए तत्काल प्रभाव से वार-रूम अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अपने विधि, मानवाधिकार और आरटीआइ विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से विधि, मानवाधिकार और आरटीआइ विभाग के पुनर्गठन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में सलमान खुर्शीद, केटीएस तुलसी, विवेक तन्खा, हरिन रावल, प्रशांतो सेन, देवदत्त कामथ और विपुल माहेश्वरी को शामिल किया गया है। कांग्रेस के विधि विभाग के कार्यकारी पैनल में मुहम्मद अली खान सचिव बनाए गए हैं।

उनके साथ ही अमन पंवार, उमर होदा, ईशा बख्शी, अर्जुन शर्मा, निशांत मंडल, अमित भंडारी, तरन्नुम चीमा, निंगोम्बम बुपेंडा मैतेयी, लालनुन्हलुई राल्ते और स्वाति ड्रैक भी कार्यकारी पैनल के सदस्य हैं।

वार-रूम अध्यक्षों की हुई नियुक्ति

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए तत्काल प्रभाव से वार-रूम अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।चल्ला वम्शी चंद रेड्डी महाराष्ट्र में, नवीन शर्मा हरियाणा में और गोकुल बुटेल जम्मू-कश्मीर में वार रूम के प्रमुख होंगे। शशिकांत सेंथिल राष्ट्रीय वार रूम के अध्यक्ष बने रहेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com

(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023